



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]
No. 131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2012/ज्येष्ठ 11, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2012/JYAISTHA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महाविदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया तथा जापान के मूल के या वहां से निर्यातित मेलामाइन के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

पृष्ठभूमि :

सं. 14/35/2010-डीजीएडी.—यतः यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को मै. टी पी एम सॉलिसिटर्स एंड कंसल्टेंट्स, नई दिल्ली के मार्फत मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जी एस एफ सी) वडोदरा (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया तथा जापान (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित मेलामाइन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

2. और यतः घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य की पर्याप्तता और यथातथ्यता की जांच करने के बाद उसके आधार पर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 7 दिसम्बर, 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ताकि आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

3. और यतः मै. सेंचुरी प्लाइबोर्ड्स (इं.) लि. ने 7 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 19.8.2011 के अपने निर्णय में निम्नानुसार उल्लेख किया : “श्री बोस ने यह तर्क दिया है कि नियम 2 (ख) में “सकता है” अभिव्यक्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास किसी आयातक को बाहर न रखने का विवेकाधिकार है”। तथापि, 27 फरवरी, 2010 की डी आर अधिसूचना सं. 18/2010-सी. शु. (एन टी) द्वारा यथासंशोधित नियम 2 (ख) से यह स्पष्ट है कि आयातकों को बाहर रखा गया है। “सिवाय” अभिव्यक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण है। “घरेलू उद्योग” को परिभाषित किया गया है जिससे समान वस्तुओं के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न ऐसे समग्र घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है, सिवाय उस स्थिति के—जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उनके आयातक हों। जहां उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं, वहां घरेलू उद्योग पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए। :

श्री बोस के तर्कानुसार “सकेगा” के स्थान पर “सकता है” रखा गया है। अतः यह सिद्धांत कि “सकता है” का अर्थ “सकेगा” के रूप में निकाला जा सकता है—लागू नहीं होगा क्योंकि नियम निर्माताओं ने अत्यंत सोच समझ कर “सकेगा” के स्थान पर “सकता है” अभिव्यक्ति को रखा है। तथापि, 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना द्वारा आगे और किए गए संशोधन इस आशय की शंका की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती है कि आयातकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी के पास यह विवेकाधिकार है कि वह “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य आयातक से इतर शेष घरेलू उत्पादकों के रूप में निकाले अथवा नहीं।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर जो जारी तौर पर और रिकॉर्ड के अनुसार आयातक हैं, के अनुरोध पर जांच की शुरुआत कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

अतः रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है। विवादास्पद अधिसूचना रद्द की जाती है”

4. और यतः मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा ने 19.8.2011 के विवादास्पद आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की। बाद में भारत सरकार ने विवादास्पद आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की। अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 21.11.2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“विवादास्पद निर्णय और आदेश इस अपील के निपटान तक स्थगित रहेगा क्योंकि अधिसूचना रद्द कर दी गई है। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वह नियमों में

निर्धारण जांच-पड़ताल के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई करें; लेकिन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए। यदि रिपोर्ट डॉ. चक्रवर्ती के मुवक्किलों के खिलाफ है तो इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उपर्युक्त आदेश पारित करते समय हमने जो विचार व्यक्त किए हैं वे एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री बनाम जे.के. इंडस्ट्रीज लि. तिआ अन्य, (2005) 11 एस एस सी पृष्ठ 482 में सूचित मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय से समर्थित है।”

5. और जबकि दिनांक 7 मई, 2012 के आदेश द्वारा डिविजन बेंच ने सरकार के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी परंतु सरकार अपील के निपटान तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

क. प्रक्रिया:

6. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावास/व्यापार प्रतिनिधि को सूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने नियम 6 के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में सूचना देते हुए 7 दिसंबर, 2010 की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां इस अनुरोध के साथ भारत स्थित संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति तथा आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण भी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों के नाम और पत्रों सहित उनके पास भेजी गई थी।
- iii. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण तथा निर्यातक प्रश्नावली के साथ 7 दिसंबर, 2010 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी और उनसे जांच शुरुआत की अधिसूचना के 40 (चालीस) दिनों के भीतर संगत सूचना प्रदान करने तथा लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने आयातक प्रश्नावली के साथ 7 दिसंबर, 2010 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार जांच शुरुआत की अधिसूचना के 40 (चालीस) दिनों के भीतर संगत सूचना प्रदान करने तथा लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- v. नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

क. पं. डी एस एम कल्टीम मेलामाइन, इंडोनेशिया

- ख. डी सी एम मेलामाइन, ई यू
- ग. डी सी एम मेलामाइन, इंडोनेशिया
- घ. एग्रोलिन्ज मेलामाइन इंटरनेशनल जी एम बी एच, ई यू
- ङ. निशान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., जापान
- च. खोरासन फार्मास्युटीकल कंपनी, ईरान
- छ. ईरान पेट्रोकेमिकल कॉमर्शियल कं., ईरान
- vi. संबंध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने जांच शुरुआत का उत्तर दिया परंतु प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया :
- क. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑन दि पब्लिक ऑफ कोरिया
- ख. पी टी ओ सी आई कलटिम मेलामाइन, इंडोनेशिया
- vii. नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबंध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी :
- क. ग्रीनप्लाइ इंड लि.
- ख. मैरीनो इंड लि.,
- ग. मैरीनो पैनल प्रोडक्ट्स लि.
- घ. गोल्डन लेमिनेट्स लि.,
- ङ. सूर्या विकास प्लाईवुड प्रा.लि.,
- च. कात्यानी कैमटेक इंडिया लि.
- छ. रूशील डेकोर लि.
- ज. सनडैक इंडिया लि.
- झ. ब्लूम डेकर लि.
- ट. एच ई एफ इंडिया प्रा.लि.
- ठ. सेचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लि.
- ड. मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लि.
- ढ. वर्गो इंडस्ट्रीज
- ण. अल्फा आइका लि.
- त. दि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी

viii. निम्नलिखित आयातकों/हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरूआत का उत्तर दिया है :

क. एग्जिमक्रॉप इंडिया प्रा.लि.

ख. सेंचुरी प्लाइवोर्ड (इंडिया) लि.

ग. इंडियन लेमिनेट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

ix. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था । डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया गया था और इसकी तुलना आई बी आई एस (गौण स्रोत) से प्राप्त सूचना के साथ की गई थी । विस्तृत जांच के बाद आई बी आई एस की सूचना पर विचार करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि उसमें उच्च मात्रा सूचित की गई थी ।

x. मै. सेंचुरी प्लाइवोर्ड्स (इं.) लि. ने 7 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की । उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 19.8.2011 के अपने निर्णय में निम्नानुसार उल्लेख किया :

“श्री बोस ने यह तर्क दिया है कि नियम 2 (ख) में “सकता है” अभिव्यक्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास किसी आयातक को बाहर न रखने का विवेकाधिकार है” । तथापि, 27 फरवरी, 2010 की डी आर अधिसूचना सं. 18/2010-सी. शु. (एन टी) द्वारा यथासंशोधित नियम 2 (ख) से यह स्पष्ट है कि आयातकों को बाहर रखा गया है । “सिवाय” अभिव्यक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण है । “घरेलू उद्योग” को परिभाषित किया गया है जिससे समान वस्तुओं के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न ऐसे समग्र घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उनके आयातक हों । जहां उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं, वहां घरेलू उद्योग पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए । :

श्री बोस के तर्कानुसार “सकेगा” के स्थान पर “सकता है” रखा गया है । अतः यह सिद्धांत कि “सकता है” का अर्थ “सकेगा” के रूप में निकाला जा सकता है-लागू नहीं होगा क्योंकि नियम निर्माताओं ने अत्यंत सोच समझ कर “सकेगा” के स्थान पर “सकता है” अभिव्यक्ति को रखा है । तथापि, 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना द्वारा आगे और किए गए संशोधन इस आशय की शंका की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती है कि आयातकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी के पास यह विवेकाधिकार है कि वह “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य आयातक से इतर शेष घरेलू उत्पादकों के रूप में निकाले अथवा नहीं ।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर जो जारी तौर पर और रिकॉर्ड के अनुसार आयातक हैं, के अनुरोध पर जांच की शुरुआत कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

अतः रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है। विवादास्पद अधिसूचना रद्द की जाती है”

- xi. और यतः मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा ने 19.8.2011 के विवादास्पद आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की। बाद में भारत सरकार ने विवादास्पद आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की। अपील पर सुनवाई करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 21.11.2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किया।

“ विवादास्पद निर्णय और आदेश इस अपील के निपटान तक स्थगित रहेगा क्योंकि अधिसूचना रद्द कर दी गई है। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वह नियमों में निर्धारण जांच-पड़ताल के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई करें; लेकिन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए। यदि रिपोर्ट डॉ. चक्रवर्ती के मुक्किलों के खिलाफ है तो इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उपर्युक्त आदेश पारित करते समय हमने जो विचार व्यक्त किए हैं वे एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री बनाम जे.के. इंडस्ट्रीज लि. तिा अन्य, (2005) 11 एस एस सी पृष्ठ 482 में सूचित मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय से समर्थित है। ”

- xii. और जबकि दिनांक 7 मई, 2012 के आदेश द्वारा डिविजन बेंच ने सरकार के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी परंतु सरकार अपील के निपटान तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
- xiii. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार कार्रवाई की।
- xiv. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा। अगोपनीय आवेदन की एक प्रति अनुरोध के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- xv. प्राधिकारी ने क्षति की जांच करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्तपादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने

की लागत निकालने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक सत्यापन किया ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

- xvi. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 6 मार्च, 2012 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए समस्त हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया । जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों पर उत्तर दायर करने का आग्रह किया गया था ।
- xvii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 09 से 30 जून, 10 (15 माह) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जांच अवधि शामिल है ।
- xviii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्य का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर संगत सीमा तक इस अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है । निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के अनुपालन में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं ।
- (क) मै. जी एस एफ सी, वदोदरा
- (ख) मै. सैंचुरी प्लाई (इं.) लिमिटेड, कोलकाता
- (ग) मै. एग्जिमक्रॉप इंडिया प्रा.लि.
- (घ) मै. इंडियन लेमिनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट्स (आई एल एम ए)
- xix. हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएं ।
- xx. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यंत बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।
- xxi. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु:

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है जो एक स्वाद रहित, गंध रहित तथा विषरोधी पदार्थ है। मेलामाइन फार्मेलडीहाइड का लेमिनेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह काफी कठोर, खरोंच, दाग, जल और ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। कुल इलेक्ट्रिकल अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले लेमिनेट में उच्च मशीनी सुदृढ़ता, अच्छी ऊष्मा प्रतिरोधात्मकता और बेहतर विद्युतरोधी गुणधर्म होते हैं। एबस्टोस से मुक्त मेलामाइन रेजिनों में उच्च डाइइलेक्ट्रिक क्षमता तथा उच्च प्रतिरोधी क्षमता होती है। सर्वोत्तम आयामी स्थिरता के अलावा, मेलामाइन का फार्मेलडीहाइड मोल्डिंग पाउडर स्पष्ट तथा चमकयुक्त रंग, आसान लोचशीलता प्रदान करता है और सतही खरोंच से बचाव करता है। सौंदर्य तथा उपयोगिता संबंधी अनेक उत्पादों को बनाने के लिए फार्मेलडीहाइड के साथ मेलामाइन की अभिक्रिया की जाती है और उसे रोल अथवा मोल्डिंग चूर्ण का रूप दिया जाता है। मेलामाइन का उपयोग मेलामाइन फोमेलडीहाइड बनाने के लिए किया जाता है जिसे बाद में अनुषंगी उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।
8. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के उपशीर्ष सं. 29336100 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

ख.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार:

9. कार्रवाई के किसी चरण पर विचाराधीन उत्पाद के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग. समान वस्तु:

10. समान वस्तु के बारे में नियम 2(घ) में निम्नानुसार उपबंध हैं: -

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादित और वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी

विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विधिवत विचार करने और उनकी जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार :

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:

क. जांच की शुरुआत के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी भी स्पष्ट रूप से यह समझते थे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कानूनन विवेकाधिकार है। अतः याचिकाकर्ता ने सूचना प्रस्तुत करते समय स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया था।

ख. याचिकाकर्ता ने आयातों को मात्र सुविधा प्रदान की है - याचिकाकर्ता ने निर्यातक से वस्तु का आर्डर दिया और समुद्र पारीय करारों/बांड के तहत उसकी बिक्री कर दी।

ग. याचिकाकर्ता ने घरेलू खपत हेतु वस्तु की निकासी के लिए कोई प्रवेश बिल दायर नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने इन आयातों को सुकर बनाया है और भंडारण हेतु लदान बिल तथा प्रवेश बिल दायर किए हैं। जी एस एफ सी के उपभोक्ताओं/ग्राहकों द्वारा घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल दायर किए गए हैं।

घ. याचिकाकर्ता ने सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य किया है ताकि ये ग्राहक पाटित वस्तु का सीधे आयात शुरू न करें और घरेलू उद्योग को दीर्घावधिक क्षति पहुंचाएं।

ङ. नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास गुण-दोष के आधार यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या ऐसी किसी कंपनी को घरेलू उद्योग के निर्धारण हेतु शामिल किया जाना चाहिए या अलग रखा जाना चाहिए जो विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही है या जो किसी निर्यातक से संबंधित है या जो स्वयं आयातक है।

च. जी एस एफ सी ने ऐसी सामग्री की बिक्री भारी मुनाफे पर नहीं की है। आम तौर पर जी एस एफ सी की नीति आयात की कीमत से तुलनीय कीमत पर सामग्री की बिक्री करने की है। तथापि मुद्रा में घट-बढ़ तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए खरीद और बिक्री कीमत में छिट-पुट अंतर हो सकता है।

छ. पाटन से लाभ उठाने के लिए आयात नहीं कर रही है। जी एस एफ सी ने ध्यान आयात पर केन्द्रित नहीं किया है। कंपनी अपना ध्यान खुद के उत्पादन पर केन्द्रित कर रही है। देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी वस्तुतः अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है।

ज. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद मै. जी एस एफ सी ने बताया है कि उन्हें एक से अधिक कारणों की वजह से आयातक नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि उन्होंने आयातों में केवल सुविधा पहुंचाई है अर्थात् याचिकाकर्ता ने निर्यातक से वस्तुओं का आदेश दिया और उन्हें एक्स बाँड आधार के जरिए बेच दिया। इसके अलावा उन्होंने पिछले अवसर पर प्राधिकारी के समक्ष की गई अपनी टिप्पणियों को दोहराया है और यह बताया कि उन्होंने उत्पाद निलंबन/रूकावट के समय या उपभोक्ताओं की अग्रिम लाइसेंस जरूरतों के तहत सामग्री के सीधे आयातों से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से इन सामग्रियों के आयात को सुगम बनाया है ताकि ये उपभोक्ता पाटित वस्तुओं के सीधे आयात को अपना न शुरू कर दें और इसके कारण से उद्योग को दीर्घावधिक नुकसान न हो।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

क. घरेलू उद्योग मानने के लिए आवेदक के पास कानून के अंतर्गत मूलभूत योग्यताएं नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों के कारण के रूप में उसके दावे के अनुसार संयंत्र को बंद किए जाने के बारे में याचिकाकर्ता ने कोई प्रकाशित सूचना तिरा कारण उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ख. याचिकाकर्ता "घरेलू उद्योग" नहीं है क्योंकि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

ग. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य के संबंध में अपने विचारों को दोहराया है कि आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग नहीं हैं। उन्होंने मै. जी एस एफ सी द्वारा किए गए दावों पर भी प्रश्न उठाया है कि वे आयातक नहीं हैं अपितु संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के सुविधाप्रदाता हैं। विभिन्न आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें संबद्ध वस्तु आवेदक द्वारा विदेशी निर्यातकों को उसकी बिक्री के प्रयोजनार्थ भुगतान के वैध आधार पर आयातित की गई है और बाँड में भंडारित या भांडागार में रखी गई है जब तक भारत में आयातक आवेदक द्वारा इसकी बिक्री न कर दी जाए। यह भी बताया गया है कि प्रचलित बाजार कीमत पर कार्गो को भंडारित करने के बाद बिक्री किए जाने से आवेदक यह दावा करने का पात्र नहीं है कि वे केवल ऐसे कारोबार में सुविधा प्रदाता थे।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. यह याचिका मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि. (जी एस एफ सी) ने दायर की थी। जांच की शुरुआत के समय नियम 2(ख) निम्नानुसार था :

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो

ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

16. दिनांक 01.12.2011. को नियम 2(ख) में संशोधन किया गया था और यह अब निम्नानुसार है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।

17. जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने ऐसे लघु ग्राहकों की जरूरतों को सुकर बनाने के लिए उनके उत्पादन में व्यवधान आने के समय आयात किए हैं जिन्होंने सामग्री का आयात करने और उसकी आपूर्ति करने के बारे में याचिकाकर्ता के समक्ष इच्छा व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि सीमाशुल्क निकासी हेतु इन आयातों के प्रवेश बिल उन्होंने दायर नहीं किए थे। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह आयातक नहीं है बल्कि उसने आयातों में केवल सुविधा प्रदान की है। कार्रवाई के दौरान मै. इंडियन लेमिनेट मैन्यु. एसो. और एग्जिम कार्प इंडिया प्रा.लि. तथा अन्य ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग मानने के लिए आवेदक के पास कानून के अंतर्गत मूलभूत योग्यताएं नहीं हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है और घरेलू उद्योग के रिकॉर्डों का मौके पर सत्यापन भी किया है तथा जांच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि

क. संबद्ध अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की घरेलू उद्योग द्वारा कोई अधिक बिक्री नहीं की गई थी। यह नोट किया जाता है कि मै. जी एस एफ सी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात करते समय भंडारण के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क में प्रवेश बिल दायर किए थे। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उन्होंने आयातित संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल दायर नहीं किए। मै. जी एस एफ सी ने उनके द्वारा आयातित संबद्ध वस्तु की बिक्री की थी और उसे विभिन्न क्रेताओं को एक्स बॉड आधार पर बेचा था।

ख. यह नोट किया गया था कि जी एस एफ सी ने बांड आधार पर आयातित उत्पाद की बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान नहीं किया है। इसके बजाए घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल दायर करने वाले अंतिम आयातक ने सीमाशुल्क, सी बी डी, एस ए डी आदि सहित आयात करों का भुगतान किया है।

ग आगे यह नोट किया गया था कि जी एस एफ सी ने लाभ हेतु अत्यधिक अभिवृद्धियों के बिना संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। रिकॉर्डों का सत्यापन करने के बाद यह नोट किया गया था कि यदि भंडारण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से जुड़े समस्त व्यय और बांड आधार पर उसकी बिक्री पर विचार किया जाए तो यह देखा जाता है कि इन खरीदों में अत्यंत मामूली (कुछ सौदों में मामूली घाटा भी हुआ है) लाभ हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि जी एस एफ सी की खरीद कीमत जांच अवधि के दौरान भारत औसत आयात कीमत से अत्यंत तुलनीय है।

घ. यह नोट किया गया था कि जांच अवधि के दौरान आयातों का हिस्सा उसके उत्पादन का लगभग 11.78%, कुल आयातों का 7.44% और भारत में खपत का 4.57% बनता है।

18. जांच की कार्यवाही के दौरान माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय ने निरमा लि. बनाम सेंटगोवेन ग्लास इंडिया लि. के मामले में यह निर्णय लिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार है और 27 फरवरी, 2010 के संशोधन के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी का उक्त विवेकाधिकार समाप्त नहीं हुआ है।

19. प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और यह माना है कि याचिकाकर्ता ने घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल दायर नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता ने भंडारण हेतु प्रवेश बिल दायर किए हैं और घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल सीधे उपभोक्ताओं ने दायर किए हैं। यद्यपि, मै. जी एस एफ सी ने संबद्ध वस्तु का आयात और बिक्री की थी तथापि, प्राधिकारी का मत है कि जी एस एफ सी का ध्यान आयात पर केन्द्रित नहीं हुआ है और कंपनी आयातक व्यापारी के समान व्यवहार नहीं कर रही है। कंपनी का ध्यान उत्पादक की हैसियत पर रहा है और उसने अपना खुद का उत्पादन किया है।

20. नियम 2(ख) की परिभाषा और उपर्युक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन में उपर्युक्त नियम के नियम 5 के अनुसार आधार के मापदंड की पूर्ति होती है।

ड अन्य मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) मेलामाइन के उत्पादन हेतु कंपनी यूरिया का प्रयोग करती है जो उर्वरक उत्पाद नहीं है। अतः प्राकृतिक गैस में शामिल दो कीमत तंत्र हैं (क) प्रशासनिक कीमत तंत्र (ए पी एन) और (ख) गैर-प्रशासनिक कीमत तंत्र (गैर-एपीएम)

(ख) भारत सरकार द्वारा अपनी खुद की कीमत पर जी एस एफ सी को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है और उर्वरक के प्रयोजन हेतु उसकी उत्पादन लागत इन कीमतों के आधार पर निर्धारित करती है। कंपनी को मेलामाइन सहित अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु इस प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कंपनी को मेलामाइन सहित ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु बाजार से खरीद करनी चाहिए।

(ग) अतः कंपनी के लिए मेलामाइन के उत्पादन और बिक्री हेतु उत्पादन की वास्तविक लागत तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि उस कीमत का निर्धारण न किया जा सके जिस कीमत पर कंपनी ने मेलामाइन के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की खरीद की है। ऐसी स्थिति में जहां कंपनी ने कई प्रयोजनों हेतु विभिन्न कीमतों पर निविष्टि की खरीद की है, वहां यह माना जाता है कि कंपनी की भारित औसत खरीद लागत, खासकर तब जब कंपनी ने अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग कीमत पर उसी निविष्टि की खरीद की है, ऐसे सभी उत्पादों के लिए निविष्टि की लागत नहीं है।

(घ) अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अमोनिया जिसकी जरूरत यूरिया के उत्पादन के लिए होती है और जिसे बाद में मेलामाइन के उत्पादन के लिए जरूरी समझा जाता है, की लागत का निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक गैस की गैर ए पी एम कीमत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उर्वरक के अंतिम उत्पादन हेतु पूर्व निर्धारित कीमत पर कंपनी को उपलब्ध कराई गई प्राकृतिक गैस इस प्रयोजनार्थ पूर्णतः अप्रासंगिक है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

(क) भारत में पेट्रोलियम फीड स्टॉक की कीमत प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में काफी अधिक है। भारतीय उद्योग ऊपरी लागत के संबंध में घाटे की स्थिति में है।

(ख) याचिकाकर्ता ने याचिका में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूर्ण सूचना का प्रकटन नहीं किया है। निम्नलिखित सूचनाएं गायब हैं:

क. आवेदन के खंड-1 में आरोपित पाटित वस्तु के प्रयोक्ताओं से संबंधित प्रश्न गायब है।

ख. आवेदन के खंड vi में प्रश्न 14 गायब है जिसमें, खरीद नीति, बिक्री नीति, भंडार लेखांकन, मालसूची/स्टॉक/डब्ल्यू आई पी मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के ब्यौरे अपेक्षित हैं।

ग. आवेदन के खंड vi में प्रश्न 10 गायब है जो लाभ/हानि से संबंधित है।

(ग) घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत काफी अधिक है । चीन जन.गण. से मेलामाइन के आयातों की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद प्राकृतिक गैस की औसत कीमत पर विचार किया था । प्राधिकारी द्वारा वर्तमान मामले में यह नीति अपनाई जानी चाहिए ।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी द्वारा विधिक उपबंधों और अपनाई जा रही प्रक्रिया पर विचार करते हुए उसने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की नीचे जांच की है :

क. जहां तक प्राकृतिक गैस की कीमत, जिसे मेलामाइन के उत्पादन हेतु अमोनिया की लागत के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए, से संबंधित मुद्दे का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के परिसर में सत्यापन के दौरान प्राधिकारी ने यह पाया कि यूरिया के उत्पादन हेतु जी एस एफ सी द्वारा अपेक्षित प्राकृतिक गैस की मात्रा सरकार से ए पी एम स्कीम के अंतर्गत प्राप्त मात्रा से काफी अधिक है । अतः कंपनी को यूरिया के उत्पादन हेतु भी गैर ए पी एम कीमत पर प्राकृतिक गैस की खरीद करनी पड़ती थी । अतः इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि जी एस एफ सी द्वारा मेलामाइन के उत्पादन हेतु ए पी एम कीमत पर कंपनी को उपलब्ध कराई गई प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है जबकि यह मात्रा यूरिया के उत्पादन के लिए भी पर्याप्त नहीं है । यह निर्विवाद है कि कंपनी को केवल उर्वरकों के उपयोग हेतु यूरिया के उत्पादन के लिए ए पी एम कीमत पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जा रही है । अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अमोनिया के निर्धारण हेतु केवल प्राकृतिक गैस की गैर ए पी एम कीमत प्रासंगिक है । अमोनिया की जरूरत यूरिया के उत्पादन के लिए होती है जिसका बाद में उपयोग मेलामाइन के उत्पादन हेतु किया जाता है ।

ख. प्राकृतिक गैस की कीमत के निर्धारण हेतु निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नीति से जुड़े तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से मेलामाइन के आयातों की निर्णायक समीक्षा के समय कानून अलग था । उस समय क्षति कीमत के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में उल्लिखित सिद्धांत कानूनन बाध्यकारी था जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागू किया था । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निविष्ट की बाजार कीमत को लिया जाना चाहिए अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु प्राकृतिक गैस की बाजार कीमत ली थी । तथापि, वर्तमान मामले में कानून में संशोधन किया गया है और अनुबंध-III लागू किया गया है जिसके अंतर्गत प्राधिकारी के लिए इस अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण करना अपेक्षित है । इसके अंतर्गत प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड पर विचार करना अपेक्षित है ।

ग. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ऊपरी लागत के बारे में घरेलू उद्योग घाटे की स्थिति में है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने समूची क्षति अवधि के दौरान इन्हीं स्थितियों में प्रचालन किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै. निप्पोन जियोन कंपनी लि., जापान तथा अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट ने यह निर्णय दिया कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रश्न आदर्श स्थितियों का अनुमान लगाकर तय नहीं किया जा सकता अपितु उसे उचित समायोजन के जरिए विद्यमान स्थितियों में तय करना होता है।

घ. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार याचिका में पूर्ण सूचना का प्रकटन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के अंतर्गत कोई आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में होना चाहिए और उसके साथ (क) पाटन (ख) क्षति, जहां लागू हो और (ग) जहां लागू हो ऐसे पाटित आयातों तथा आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का साक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा नियमों में यह उपबंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्राप्त आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच शुरू नहीं करेंगे जब तक कि प्राधिकारी आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जांच न कर लें और स्वयं को इस बात से संतुष्ट न कर लें कि जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पाटन, क्षति तथा ऐसे पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य है।

च. पाटन मार्जिन की गणना की कार्य प्रणाली:

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं।

क. संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की कोई सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।

ख. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने उपलब्धता के अनुसार संबद्ध देशों की आयात कीमत के अनुसार यूरिया की कच्ची सामग्री की कीमत ली है। ईरान के मामले में ईरान के सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु जापान के लिए मध्य पूर्व (कतर) से निर्यात कीमत ली गई है।

ग. किसी भी विदेशी उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

घ. सभी चारों देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है अपितु काफी ज्यादा भी है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं।

क. याचिकाकर्त ने ईरान को छोड़कर परिकलन पद्धति के आधार पर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और कलेंडर वर्ष 2009 (12 माह) के दौरान यूरिया की वास्तविक आयात कीमत के आधार पर कच्ची सामग्री की कीमत ली गई है न कि जांच अवधि के दौरान प्रचलित आयात कीमत के आधार पर ।

ख. ईरान को छोड़कर संबद्ध देशों में सभी उत्पादक सार्वजनिक कंपनियां हैं जिनके खातों का प्रकाशन किया जाता है । जिनका उपयोग सामान्य मूल्य के निर्धारण में किया जा सकता था ।

च.3 संबद्ध देशों का सामान्य मूल्य

25. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है । वस्तुतः किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी के समक्ष सामान्य मूल्य का कोई अनुमान या साक्ष्य (घरेलू उद्योग को छोड़कर) रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं कराया है । अतः पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत ई यू, ईरान, इंडोनेशिया एवं जापान से संबद्ध वस्तु के बारे में सामान्य मूल्य का परिकलन करने की जरूरत है ।

26. संबद्ध देशों से मेलामाइन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है ।

(क) विश्व से हुए आयातों के बारे में डब्ल्यू टी ए आयात आंकड़ों के आधार पर यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार किया गया है । ईरान के मामले में डब्ल्यू टी ए में यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत उपलब्ध नहीं है । अतः भारत के लिए ईरान से निर्यात कीमत उचित समायोजन के बाद स्वीकार की गई है । सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग संबंधी मापदंड पर विचार किया गया है ।

(ख) उपयोगिताओं की लागत, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और ब्याज पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर विचार किया गया है ।

(ग) उचित लाभ हेतु ब्याज को छोड़कर 5% बिक्री लागत की अनुमति दी गई है ।

27. उपर्युक्त आधार पर संगणित सी एन वी निम्नानुसार है:

देश	सामान्य मूल्य रु./मी.ट	सामान्य मूल्य अम.डा./मी.ट
ई यू	***	***
ईरान	***	***
इंडोनेशिया	***	***

जापान	***	***
-------	-----	-----

संबद्ध देशों की निर्यात कीमत

28. संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। संबंधित निर्यातकों से असहयोग को देखते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सी आई एफ निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु संबद्ध देशों से आयातों के लिए आई बी आई एस द्वारा सूचित आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर समायोजन किया गया है। उपर्युक्त तरीके को अपनाते हुए निवल निर्यात कीमत की गणना निम्नलिखित तालिका के अनुसार की गई है।

देश	निवल निर्यात कीमत रु./मी.ट	निवल निर्यात कीमत अम.डा./मी.ट
ई यू	54,124	1,130
ईरान	50,640	1,058
इंडोनेशिया	57,198	1,195
जापान	57,401	1,199

च.4 पाटन मार्जिन का निर्धारण:

29.. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है:

	इकाई	ईयू	ईरान	इंडोनेशिया	जापान
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	1,130	1,195	1,058	1,199
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज %	25-35	25-35	20-30	40-50

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण:

31. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए" ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

छ.1. घरेलू उद्योग के विचार:

33. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :-

- क. जांच की शुरुआत के बाद लगभग 15 माह का समय बीत गया है और इसलिए संगत सूचना दायर करने में जांच शुरुआत के बाद विरोधी पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है । अतः इस चरण में विरोधी पक्षकार की ओर से अनुरोध दायर करने हेतु और अधिक समय का अनुरोध करना जांच में विलंब करने के लिए विरोधी पक्षकार की ओर से दुराशयपूर्ण मंशा के सिवाय कुछ नहीं है ।
- ख. आई एल एम ए का कुल अनुमानित आकार 3300 करोड़ रूपए का है इसलिए कोई उद्योग लघु उद्योग नहीं हो सकता ।
- ग. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु हेतु पाटन मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक है ।
- घ. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है ।
- ड. आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं ।

- च. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद आपस में और याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित उत्पाद की तुलना में तुलनीय गुणधर्म रखते हैं । दूसरे शब्दों में संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त वस्तु समान वस्तु है ।
- छ. ऐसे सीमित पक्षकार हैं जो इस सामग्री का उपयोग करते हैं । समान ग्राहकों द्वारा आयातित और घरेलू सामग्री का अदल-बदल कर उपयोग किया जा रहा है ।
- ज. संबद्ध देशों के निर्यातकों और याचिकाकर्ता ने उन्हीं ग्राहकों को उन्हीं अवधियों में उसी उत्पाद की बिक्री की है ।
- झ. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा न्यूनतम सीमा से अधिक है ।
- ञ. घरेलू उत्पादक और संबद्ध देशों के निर्यातक समान उपभोक्ता श्रेणी को समान उत्पाद की बिक्री करते हैं और ये दोनों समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं । उपभोक्ताओं द्वारा दोनों का अदल-बदल कर उपयोग किया जा रहा है ।
- ट. कंपनी द्वारा मेलामाइन के उत्पादन हेतु यूरिया का उपयोग किया जाता है जो कि उर्वरक उत्पाद नहीं है । अतः प्राकृतिक गैस में शामिल दो कीमत तंत्र हैं (क) प्रशासनिक कीमत तंत्र (ए पी एम) और (ख) गैर प्रशासनिक कीमत तंत्र (गैर ए पीएम)
- ठ. भारत सरकार द्वारा अपनी खुद की कीमत पर जी एस एफ सी को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराती है और उर्वरक के प्रयोजन हेतु उसकी उत्पादन लागत इन कीमतों के आधार पर निर्धारित करती है । कंपनी को मेलामाइन सहित अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु इस प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की अनुमति नहीं है । कंपनी को मेलामाइन सहित ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु बाजार से मेलामाइन की खरीद करनी चाहिए ।
- ड. अतः कंपनी के लिए मेलामाइन के उत्पादन और बिक्री हेतु उत्पादन की वास्तविक लागत तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि उस कीमत का निर्धारण न किया जा सके जिस कीमत पर कंपनी ने मेलामाइन के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की खरीद की है । ऐसी स्थिति में जहां कंपनी ने कई प्रयोजनों हेतु विभिन्न कीमतों पर निविष्टि की खरीद की है, वहां यह माना जाता है कि कंपनी की भारित औसत खरीद लागत, खासकर तब जब कंपनी ने अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग कीमत पर उसी निविष्टि की खरीद की है, ऐसे सभी उत्पादों के लिए निविष्टि की लागत नहीं है ।
- ढ. अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अमोनिया जिसकी जरूरत यूरिया के उत्पादन के लिए होती है और जिसे बाद में मेलामाइन के उत्पादन के लिए जरूरी समझा जाता है, की लागत का निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक गैस की गैर ए पी एम कीमत को ध्यान में रखा जाना चाहिए क। उर्वरक के अंतिम उत्पादन हेतु पूर्व निर्धारित कीमत पर कंपनी को उपलब्ध कराई गई प्राकृतिक गैस इस प्रयोजनार्थ पूर्णतः अप्रासंगिक है ।

- ण. वर्ष 2008-09 में मामूली गिरावट के साथ समूची क्षति अवधि के दौरान देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है ।
- त. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है ।
- थ. आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है ।
- द. संबद्ध देशों से आयात के हिस्से में भारत में मांग की तुलना में वृद्धि हुई है ।
इसके अलावा, घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।
- ध. आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है ।
- न. जांच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम रही थी ।
- प. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है । कीमत में इस कटौती के परिणामस्वरूप आयातों के कारण भारत में घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हो रहा है ।
- फ. वर्ष 2007-08 से घरेलू उद्योग के उत्पादन और परिणामतः क्षमता उपयोग में गिरावट शुरू हुई है । घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भारत में उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी चाहिए थी । परंतु जांच अवधि में उसमें भारी गिरावट आई है । पाटित आयातों ने घरेलू कीमत में कटौती कर मांग में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया है । पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग न केवल अपनी उत्पादन क्षमता का पर्याप्त उपयोग करने से वंचित हुआ है अपितु घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपने उपयोग को न्यूनतम स्तर तक घटाने के लिए बाध्य हुआ है । अतः पाटन से घरेलू उद्योग को अत्यधिक मात्रात्मक क्षति हुई है ।
- ब. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट आई है । इसके अलावा, जांच अवधि में बिक्री मात्रा में आधार वर्ष से 20% की गिरावट आई है ।
- भ. यूरिया की कीमत में घट-बढ़ के कारण घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत में कमी या वृद्धि की है । वर्ष 2007-08 के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है । संबद्ध देशों से अत्यधिक कम कीमत पर पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण याचिकाकर्ता अपनी बिक्री में उसी दर से वृद्धि नहीं कर सका । परिणामतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2007-08 में सुधार हुआ और उसके बाद उसमें भारी गिरावट आई ।
- म. निवेश पर आय और नकद प्रवाह में लाभ जैसी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।
- य. जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के

बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है और आयातों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

- र. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में भारी वृद्धि हुई है ।
- व. क्षति अवधि के दौरान बिक्री मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग में नकारात्मक वृद्धि हुई है जबकि बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभप्रदता आदि में वर्ष 2008-09 तक सकारात्मक वृद्धि हुई है और पाटित आयातों के कारण 2008-09 तथा जांच अवधि में यह नकारात्मक बन गई है ।
- श. घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।
- ष. याचिकाकर्ताओं ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अलग-अलग पत्रों की प्रतियां निम्नलिखित उल्लेख के साथ दायर की हैं :-
- क. सब्सिडी को सीमित करने के लिए निविष्टि के सबसे सस्ते स्रोत का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
- ख. कंपनी की उत्पादन योजना है (प्राकृतिक गैस की व्यवस्था और विनियमन करने के लिए) । उर्वरकों से इतर प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा यूरिया का कोई अतिरिक्त उत्पादन किसी सब्सिडी या रियायती दर का पात्र नहीं है ।
- ग. उर्वरकों के उत्पादन हेतु ऊर्जा की खपत के मानक निर्धारित करना जिससे आगे उस इकाई को कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी ।
- घ. बहु उत्पाद कंपनियों के मामले में ए पी एम गैस की अनुमति केवल सब्सिडीशुदा उर्वरक कार्यकलापों के लिए प्रदान की जानी है ।
- ङ. उर्वरकों से इतर उत्पादों के विनिर्माण हेतु हमारी जैसी इकाइयों द्वारा प्रयुक्त ए पी एम गैस के लिए बाजार कीमत वसूली जानी चाहिए ।
- च. ए पी एम गैस की आपूर्ति केवल विद्युत और उर्वरक खंड को की जाएगी ।

प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद घरेलू उद्योग के विचार

34. पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे के बारे में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(i) घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती अवसर पर प्राधिकारों के समक्ष किए गए अनुरोधों को दोहराया है विशेष रूप से उन्होंने बताया है कि मेलामाइन के उत्पादन में प्रमुख निविष्टि के रूप में यूरिया की जरूरत होती है । यूरिया का उत्पादन एक निविष्टि के रूप में अमोनिया के प्रयोग द्वारा किया

जाता है। इसके बाद अमोनिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस अपेक्षित होती है। जी एस एफ सी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर उर्वरक की बिक्री की है। उर्वरकों की उत्पादन लागत और भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कीमत के बीच के अंतर का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने इसे एक सब्सिडी माना है। यद्यपि, यह कंपनी द्वारा बाजार से प्रभावित की जाने वाली कीमत और वह कीमत जिस पर कंपनी ने उत्पाद का बिल तैयार किया है, के बीच के अंतर के अलावा कुछ भी नहीं है। यह "सब्सिडी" केवल उर्वरक प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक गैस पर भारत सरकार द्वारा दी जाती है। कंपनी मेलामाइन के उत्पादन हेतु यूरिया का उपयोग करती है जो एक उर्वरक उत्पाद नहीं है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस में कीमत के दो तंत्र शामिल हैं :- (क) प्रशासनिक कीमत तंत्र (ए पी एम) और (ख) गैर-प्रशासनिक कीमत तंत्र (गैर-एपीएम)। भारत सरकार जी एस एफ सी को अपनी स्वयं की कीमतों पर प्राकृतिक गैस प्रदान करती है और इन कीमतों के आधार पर उर्वरक प्रयोजनों के उत्पादन लागत निर्धारित करती है। कंपनी को इस प्राकृतिक गैस के उपयोग की मेलामाइन सहित अन्य उत्पादों का उत्पादन करने हेतु अनुमति नहीं है। कंपनी को मेलामाइन सहित ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए बाजार से मेलामाइन खरीदने चाहिए अतः उत्पादन के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत और कंपनी के लिए मेलामाइन की कीमत तब तक निर्धारित नहीं हो सकती जब तक वह कीमत ना पता चले जिस पर कंपनी ने मेलामाइन के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की खरीद की है। ऐसी स्थिति में जिसमें कंपनी ने एक निविष्टि को अनेक प्रयोजनों हेतु अनेक कीमतों पर खरीदा है। यह स्पष्ट है कि कंपनी की भारित औसत खरीद लागत ऐसे सभी उत्पादों विशेष रूप से तब जबकि कंपनी ने भिन्न-भिन्न उत्पादों के लिए भिन्न-भिन्न कीमतों पर समान निविष्टि को खरीदा है, निविष्टि की लागत नहीं है। अतः क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक गैस की गैर ए पी एम कीमत को अमोनिया की लागत निर्धारित करने हेतु किया जाना चाहिए जो यूरिया के उत्पादन के अपेक्षित है जिसकी जरूरत मेलामाइन के उत्पादन में होती है। प्राकृतिक गैस कंपनी को उर्वरक के अंतिम उत्पादन हेतु पूर्व निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराया जाना इस प्रयोजनार्थ पूर्णतः असंगत है।

ii. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग के लिए यूरिया की खपत कीमत वस्तुतः कुछ संबद्ध देशों में प्रचलित यूरिया की कीमत से तुलनीय (या कम भी) है इस प्रकार यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की यूरिया की खपत कीमत अधिक है। ऐसे मामले में इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि कंपनी की प्राकृतिक गैस की औसत खपत कीमत (जो विचाराधीन उत्पाद तथा गैर विचाराधीन उत्पाद की खपत को भी दर्शाती है) को वर्तमान प्रयोजनार्थ अपनाया जाना चाहिए।

iii. यह भी अनुरोध किया गया है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि कंपनी द्वारा निर्धारित लागत कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों पर आधारित नहीं है। यह लागत वस्तुतः कंपनी के रिकॉर्डों पर भी आधारित है। तथापि, जब कंपनी अनेक उत्पादों का उत्पादन कर रही है जिसके लिए वह अनेक निविष्टियां खरीद और उपभोग कर रही है तो प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कंपनी द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों की लागत और कीमतों पर विचार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार

निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद के लाभ पर विचार करना अपेक्षित है। कंपनी या उसकी इकाई या प्रभाग का लाभ पूर्णतः असंगत है।

iv. यह अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को इस प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं, अमरीकी डॉलर/किग्रा. के रूप में व्यक्त ढंग से पाटनरोधी शुल्क की मात्रा यथानिर्धारित रूप से लागू की जाए (शुल्क का निर्धारित रूप) यह अपेक्षित है क्योंकि प्राकृतिक गैस की कीमतें और उसके परिणामस्वरूप यूरिया की कीमतें जांच अवधि के पश्चात काफी बढ़ गई हैं। प्राकृतिक गैस की कीमत इस समय 17 रूपए प्रति एस एम3 है जबकि जांच अवधि के दौरान यह 11.87 रूपए प्रति एस एम थी। इस प्रकार केवल इस आधार पर उत्पादन लागत 8200 रूपए पी एम टी बढ़ गई है। ऐसे मामले में शुल्क का कोई अन्य रूप (नियत या मूल्यवर्धित को छोड़कर) शुल्क का निष्प्रभावी रूप साबित होगा और इससे पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी। प्राकृतिक गैस की कीमतों और वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, अमरीकी डॉ. की मूल्य वृद्धि का सीधा प्रभाव उत्पादन लागत पर पड़ता है।

निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :-

- क. क्षति रहित कीमत का परिकलन वास्तविक प्रभाव के साथ किसी संबंध के बिना अपितु अनुमान के अनुसार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रमुख निविष्टि यूरिया की भारत औसत लागत घटा प्राप्त सब्सिडी को लागत के परिकलन हेतु हिसाब में लिया जाए।
- ख. कच्ची सामग्री में ऐसी बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद आवेदक ने पर्याप्त और रिकॉर्ड लाभ प्राप्त किया है।
- ग. घरेलू उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ है और विश्व भर में मांग-आपूर्ति में अंतर है। आयात इस अंतर को भरने के लिए किए जाते हैं।
- घ. याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है। कोई कीमत ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं है।
- ङ अगोपनीय याचिका गोपनीय याचिका की अनुकृति नहीं है। जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यह उल्लेख है कि सीमाशुल्क निकासी हेतु इन आयातों के लिए उन्होंने प्रवेश बिल दायर नहीं किए थे।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत काफी अधिक है। चीन जन.गण. से मेलामाइन के आयातों की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद प्राकृतिक गैस की औसत कीमत पर विचार किया था। प्राधिकारी द्वारा वर्तमान मामले में यही नीति अपनानी चाहिए।

- छ. उत्पादन की प्रति इकाई उपयोगिता खपत में वृद्धि हुई है और उपरोक्त उपयोगिताओं में ऐसी वृद्धि के लिए आरोपित पाटन को कारण नहीं माना जा सकता और न ही माना जाना चाहिए ।
- ज. क्षमता संबंधी अड़चनों के कारण याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की पूर्ति नहीं कर सकता ।
- झ. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।
- ञ. ऐसा कोई कारण नहीं है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को उत्पादन में व्यवधान के कारण क्षति क्यों नहीं हुई है । इसके अलावा, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उपयोगिताओं की खपत अर्थात् विद्युत, भाप में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- ट. यदि कोई आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किया जाता है तो उसे कुल आयातों में से अलग रखा जाना चाहिए ।
- ठ. यूरिया की निविष्टि की लागत वह होनी चाहिए जिसे संबंधित अवधि में स्टॉक के अंतिम मूल्य के अनुरूप कंपनी के वित्तीय विवरण में अपनाया गया है ।
- ड. इंडोनेशियाई बाजार में प्रचलित कीमत प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था जो पाटन की गणना हेतु खुला एवं पारदर्शी बाजार है ।
- ढ. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार संबद्ध वस्तु सहित याचिका की निवल बिक्री में वृद्धि हुई है और बेहतर मुनाफा कमाया है । वर्ष 2010 में कोई मंदी आर्थिक मंदी के कारण आई है जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है ।
- ण. कंपनी 92% क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रही है और स्टॉक घटकर न्यूनतम स्तर पर आ गया है और ऐसे केवल कुछ उद्योग हैं जिन्होंने ऐसा उच्च स्तर प्राप्त किया हो ।
- त. कोई घाटा दावा किए गए कीमत प्रभाव के बजाए प्रमुख यूरिया फीड स्टॉक की लागत को बढ़ाने के लिए किए गए लागत समायोजन के कारण हुआ है ।
- थ. बिक्री प्रवृत्ति की लागत में यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में घट-बढ़ का प्रदर्शन नहीं होता है । इंडोनेशिया की कीमत घरेलू उद्योग की तुलना में फीड स्टॉक में घट-बढ़ से मिलती-जुलती है । मेलामाइन का बाजार उन कंपनियों के लिए सहायक नहीं है जो यूरिया की लागत प्रवृत्ति का पालन नहीं करती हैं ।
- द. बाजार हिस्से में गिरावट खपत में वृद्धि तथा इस वृद्धि को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आई है ।
- ध. घरेलू उद्योग की लागत यूरिया की कीमत में गिरावट से काफी अधिक है और इसकी वजह से लाभप्रदता में संबंधित हानि हुई है ।
- न. किसी कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है ।
- प. जांच अवधि के दौरान क्षति याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण बिक्री नीति के कारण हुई है । यदि याचिकाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अपनाता तो कोई क्षति नहीं होती ।

फ. विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई कीमत पाटनरोधी कानून के अंतर्गत राहत प्राप्त करने का आधार नहीं है ।

ब. जांच अवधि का कोई औचित्य नहीं है जो 12 माह की अवधि से अधिक है ।

प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् निर्यातक, आयातक और प्रयोक्ता तथा एसोसिएशन के बिचार

36. पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:

(i) वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर और इस तथ्य के मद्देनजर भी कोई क्षति नहीं हुई है कि निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) उच्चतम संभव एन आई पी से अधिक है । एन एस आर उत्पादन लागत से भी अधिक है । ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की बात छोड़िए उसे कोई क्षति नहीं हो सकती । अतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में भारी गलती की है । यह बताया गया है कि प्राधिकारी को गणनाओं में हुई भारी त्रुटियों के मद्देनजर क्षति निर्धारण पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित अन्य क्षति संबंधी मापदंडों के मुद्दे पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

(iii) प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य को इसके सिद्धांतों के साथ प्रकट किया जाना चाहिए ।

(iv) घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के निर्धारण के मुद्दे पर यह अनुरोध किया गया है कि इसकी गणना के ब्यौरे प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए जाने चाहिए विशेष रूप से उन्होंने प्राधिकारी से इस प्रकटन का अनुरोध किया है कि क्या फीड स्टॉक के रूप में प्राप्त अमोनिया के मूल्य को मेलामाइन की उत्पादन लागत से घटाया गया है और यदि अमोनिया के लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है तो उसे अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले लिया जाएगा ।

(v) आयात आंकड़ों को आई बी आई एस स्रोत से लेने के मुद्दे पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने मुद्दे उठाए हैं । इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी को आयात की सही मात्रा की गणना के लिए प्रारंभिक स्रोतों से आंकड़ों पर विचार करना चाहिए ।

(vi) हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध उत्पाद के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस के लिए ए पी एम कीमत पर पुनर्विचार करने के संबंध में अपनी पूर्ववर्ती टिप्पणियों को दोहराया है । यह भी बताया गया है कि निर्यात कीमत का विश्लेषण घरेलू उद्योग की मानित कीमत पर आधारित नहीं होना चाहिए ।

(vii) यह भी बताया गया है कि इस प्रकार से संबद्ध देशों के समस्त निर्यातों को पाटित निर्यात मान लिया गया है ।

(viii) यह भी अनुरोध किया गया है कि एन आई पी की गणना के प्रयोजनार्थ और क्षति विश्लेषण के लिए यूरिया की लागत शीट को जांच अवधि के दौरान अमोनिया की बाजार कीमत पर विचार करते हुए बनाया गया है और मेलामाइन के लिए एन आई पी यूरिया की इस प्रकार परिकलित लागत के आधार पर ज्ञात की जानी चाहिए ।

(ix) यह अनुरोध किया गया है कि कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए ये वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहीं किया गया है ।

(x) जांच अवधि के दौरान विनिमय दर की तुलना में जांच अवधि के पश्चात अमरीकी डॉलर की विनिमय दर में हुई भारी वृद्धि के मद्देनजर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे लगाना अपेक्षित हो तो भारतीय रूपए में संदर्भ कीमत के आधार पर अनुशंसित किया जाना चाहिए ।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच:

37. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे विधि प्रावधानों और परंपरा पर विचार करते हुए उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की निम्नानुसार जांच की है ।

38. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि जी एस एफ एस भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ है और मांग तथा आपूर्ति में भारी अंतर है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार व्यवहारों को दूर करना है न कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिबंध लगाना है । यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । प्राधिकारी इस संबंध में अपने पिछले सुसंगत दृष्टिकोण का उल्लेख करते हैं और वे डी एस एम इडेमुत्सु लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं । यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहते हैं तो ऐसा सामान्य मूल्य के समतुल्य कीमत पर और न कि पाटित कीमत पर जरूरत का निर्यात करके किया जा सकता है । जांच की कार्यवाही के दौरान यह नोट किया जाता है कि जी एस एफ सी द्वारा 7000 करोड़ रूपए के निवेश से दहेज, गुजरात में एक समेकित उर्वरक तथा पैट्रोरसायन कॉम्प्लैक्स की स्थापना की जा रही है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है । भूमि आवंटन तथा निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है । इस कॉम्प्लैक्स में अन्य उर्वरक तथा पैट्रोरसायन की उत्पादन क्षमता के अलावा, मेलामाइन की 40,000 एम टी पी ए की क्षमता होगी । अतः कंपनी भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है । इसके अलावा, पाटित आयातों का प्रभाव जी एस एफ सी द्वारा भारत में स्थापित की जा रही

अतिरिक्त क्षमताओं के वाणिज्यीकरण पर पड़ेगा क्योंकि उत्पादक बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण अतिरिक्त क्षमताओं के लिए बाजार ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यदि विचाराधीन उत्पाद का बाजार उचित नहीं है तो उसका निवेश अलाभकारी बन जाएगा । घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यदि उत्पाद की कीमत अर्जित रूप से इतनी कम रहती है तो संयंत्र की स्थापना करना अव्यावहारिक होगा ।

39. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिका का अगोपनीय रूपांतरण गोपनीय रूपांतरण की प्रतिकृति नहीं है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का मिलान याचिका के अगोपनीय रूपांतरण से किया है । याचिका दायर करने से लेकर जांच की शुरूआत तक कई कदम/विचार-विमर्श शामिल होते हैं । समस्त संगत सूचना सार्वजनिक फाइल में रिकॉर्ड में उपलब्ध है । समस्त संगत सूचना पर विचार करने के बाद और पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य की मौजूदगी के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उपरांत प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू की है । यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों से संबंधित मुद्दे को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने चुनौती दी है और घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों के बारे में विस्तृत सूचना और घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने हेतु औचित्य उपलब्ध कराया है । इस मुद्दे का इस जांच परिणाम के संगत शीर्षों में विस्तृत विश्लेषण किया गया है ।

40. जहां तक शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए निर्यातों के अपवर्जन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की यह सुसंगत प्रक्रिया रही है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु शुल्क छूट के अंतर्गत किए गए आयातों को शामिल किया जाए ।

41. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड लाभ सृजित किया है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच मेलामाइन से संबंधित है और क्षति संबंधी समस्त विश्लेषण मेलामाइन उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर किए गए हैं । जी एस एफ सी एक बहु उत्पाद कंपनी है और वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया कोई विवरण तब तक संगत नहीं है जब तक कि वह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित न हो । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांचें उत्पाद विशिष्ट जांचें होती हैं न कि कंपनी विशिष्ट जांच । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के रिकॉर्डों के सत्यापन के बाद क्षति मापदंडों की जांच की है और जांच के बाद परवर्ती पैराग्राफों में क्षति मापदंडों का विश्लेषण किया गया है ।

42. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि बिक्री लागत प्रवृत्ति में यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में घट-बढ़ का पता नहीं चलता है, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की यूरिया की आयात और निर्यात कीमत का विश्लेषण किया है और उसकी तुलना घरेलू उद्योग की लागत के साथ की है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है । यह नोट किया जाता है कि बिक्री लागत के निर्धारण हेतु याचिकाकर्ता द्वारा विचारित यूरिया की कीमत यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अथवा प्रत्येक संबद्ध देश में प्रचलित कीमत की तुलना में वस्तुतः कम है ।

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल'09- जून'10
----------	-------	---------	---------	---------	----------------------

क	घरेलू उद्योग - लागत (गैर-एपीएम)	9,110	10,234	13,457	12,276
	सूचीबद्ध	100	112	148	135
ख	यूरिया की आयात कीमत				
1	भारत	10,323	12,319	19,646	11,458
2	ई यू	11,538	13,774	21,074	14,391
3	इंडोनेशिया	8,016	5,109	25,686	15,524
4	ईरान	5,775	-	-	13,999
5	जापान	14,108	15,852	27,528	17,557
ग	यूरिया की निर्यात कीमत				
1	भारत	13,230	25,221	30,572	16,523
2	ई यू	10,302	13,230	22,563	12,613
3	इंडोनेशिया	11,079	12,638	29,740	15,816
4	ईरान	-	-	-	12,912
5	जापान	52,404	40,969	38,960	43,949

43. जहां तक संबद्ध जांच हेतु प्राधिकारी द्वारा चुनी गई 15 माह की जांच अवधि से जुड़े तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इसका चयन इस सुसंगत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जांच अवधि सामान्यतः जांच शुरुआत की तारीख की निकटवर्ती होनी चाहिए और यह भी सच है कि इसमें घरेलू उद्योग के पूरे एक वित्त वर्ष के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है ।

44. सार्वजनिक सुनवाई और प्रकटन विवरण के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकारी द्वारा जांच

i. हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के अनुसरण में क्षति संबंधी मापदंड और क्षति रहित कीमत के निर्धारण पर अंतिम जांच परिणाम को रखे जाने से पहले उनकी पुनः जांच की गई है । इसके अलावा, क्षति संबंधी विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप से किया गया है और क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष निकाले गए हैं और उचित शीर्षों में उल्लिखित हैं । यह कहना गलत है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्धारित एन आई पी संबद्ध वस्तु की निवल बिक्री कीमत से कम है । यह भी नोट किया जाता है कि क्षति संबंधी समस्त सूचना की वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण किया गया है और निष्कर्ष उचित शीर्षों में क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित सभी मापदंडों की जांच के पश्चात निकाले गए हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ए आर के भीतर यथाप्रदत्त उत्पादन लागत में लाभ शामिल नहीं हैं और यह जांच अवधि से संबंधित नहीं है ।

ii. जहां तक सामान्य मूल्य से संबंधित सिद्धांतों का संबंध है, उन्हें उचित शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है । सामान्य मूल्य को इस कारण से गोपनीय रखा गया है कि परिकलित

सामान्य मूल्य के कुछ तत्व घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत गोपनीय सूचना से लिए गए हैं और इसलिए उन्हें गोपनीय रखा गया है ।

iii. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत के निर्धारण के मुद्दे पर यह नोट किया जाता है कि इन्हें यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर परिकलित किया गया है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि फील्ड स्टॉक के रूप में रिकॉर्ड किए गए अमोनिया के मूल्य को एन आई पी के निर्धारण हेतु मेलामाइन की उत्पादन लागत से घटा दिया गया है ।

iv. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु क मात्रा और मूल्य को कवर करने वाले आयात आंकड़ों पर विचार करने के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह आई बी आई एस के आंकड़ों से लिए गए हैं क्योंकि उक्त आंकड़े जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की भारी मात्राओं को दर्शाते हैं ।

v. पाटन मार्जिन और क्षति विश्लेषण के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ली गई निर्यात कीमत के सही होने के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इसकी पुनः जांच की गई है ।

vi. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के समय संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की ए पी एम कीमत पर पुनर्विचार करने के मुद्दे पर यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे पर पहले ही उचित पैराग्राफों में विचार किया गया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि सभी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किए गए हैं । इसके मदेनजर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की समस्त मात्रा को क्षति विश्लेषण में पाटित आयात माना गया है ।

vii. घरेलू उद्योग के एकाधिकारी व्यवहार के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच की है और जांच के बाद यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य समान्यतः पाटन जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, को समाप्त करना और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है । एकाधिकारी माहौल सृजित करने के आरोप के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लागू करने या अन्यथा की सिफारिश करने से पहले पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध निर्धारित करते हैं । पाटनरोधी नियमों के अनुसार यह उल्लिखित नहीं है कि कोई कंपनी यदि एकाधिकारिक भी हो तो अनुचित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी की कार्रवाई हेतु अनुरोध करने से वर्जित नहीं है ।

viii. इस संबद्ध जांच परिणाम के लिए शुल्क संरचना के मुद्दे पर घरेलू उद्योग तथा आयातकों और प्रयोक्ताओं, दोनों के तर्कों पर विचार किया गया है । यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण. से इसी उत्पाद के पूर्ववर्ती मामले में पाटनरोधी शुल्क संदर्भ

कीमत आधार पर लगाया गया है । संबद्ध मामले में भी इस संबद्ध जांच परिणाम में उसी शुल्क संरचना को अपनाना उचित माना गया है ।

क्षति का संचयी निर्धारण

45. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) के अनुसार जब एक से अधिक देश से हुए किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करे कि : (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों की 3% से अधिक है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3% से कम है वहां आयातों का संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक है, और (ख) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है । प्राधिकारी ने यह पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के बारे में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा भी 3% से अधिक है ।

46. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों तथा आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात समान टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत किया गया है;
- ख. प्राधिकारी ने यह पाया है कि आयातित संबद्ध वस्तु घरेलू रूप से उत्पादित मेलामाइन की वाणिज्यिक स्थानापन्न है ।
- ग. प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना से यह उचित संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से किए गए निर्यात समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि ये समान उत्पाद हैं ।
- घ. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण वर्तमान मामले में उचित नहीं होगा ।

47. अतः क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु की पाटित आयातों के संचयी प्रभाव तथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, कीमत तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

48. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा

और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

49. चूंकि संबद्ध देशों से आयातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, इसलिए संबद्ध देशों से हुए समग्र निर्यातों को क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है ।

50. तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

छ.4 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव:

51. डी जी सी आई एंड एस से संबद्ध वस्तु के आयातों की सौदेवार सूचना मांगी गई थी और उसकी तुलना आई बी आई एस (गौण स्रोत) द्वारा प्रदत्त सूचना के साथ की गई थी । विस्तृत जांच के बाद आई बी आई एस की सूचना पर विचार करने का निर्णय लिया गया था कि इसमें उच्चतर मात्रा सूचित की गई थी ।

आयात, मांग, मात्रा और बाजार हिस्सा:

52. देश में उत्पाद की मांग का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और समस्त स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया गया था ।

संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से हुए आयात

53. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में भारी वृद्धि हुई है जबकि समूची क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात काफी कम हुए हैं और इनमें मामूली वृद्धि हुई है ।

आयातों का बाजार हिस्सा

54. संबद्ध देशों, पाटनरोधी शुल्क के अधीन देखों तथा अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का उल्लेख नीचे किया गया है । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात नगण्य हैं । कुल आयातों के बाजार हिस्से के बारे में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में मामूली गिरावट आई है जबकि पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है ।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-	2008-09	जांच	जांच अवधि
-------	------	---------	-------	---------	------	-----------

			08		अवधि	वार्षिकीकृत
आयात	मी.ट.	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153
ई यू	मी.ट.	302	662	1,144	6,443	5,154
इंडोनेशिया	मी.ट.	2,787	6,665	989	3,801	3,041
ईरान	मी.ट.	453	2,761	1,421	7,420	5,936
जापान	मी.ट.	980	840	280	2,160	1,728
संबद्ध देश	मी.ट.	4,522	10,928	3,833	19,824	15,859
पहले से पाटनरोधी शुल्क के अधीन चीन	मी.ट.	1,612	5,104	8,867	8,894	7,115
अन्य देश	मी.ट.	140	430	220	223	178
आयातों में बाजार हिस्सा						
ई यू	%	4.81	4.02	8.85	22.26	22.26
इंडोनेशिया	%	44.42	40.49	7.66	13.13	13.13
ईरान	%	7.22	16.77	11.00	25.64	25.64
जापान	%	15.62	5.10	2.17	7.46	7.46
संबद्ध देश	%	72.07	66.38	29.67	68.50	68.50
पहले से पाटनरोधी शुल्क के अधीन चीन	%	25.70	31.00	68.63	30.73	30.73
अन्य देश		2.23	2.61	1.70	0.77	0.77

मांग संबंधी विवरण:

55. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008-09 में गिरावट जो मंदी के कारण हो सकती है, के साथ समूची क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
आयात	मी.ट.	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153
ई यू	मी.ट.	302	662	1,144	6,443	5,154
इंडोनेशिया	मी.ट.	2,787	6,665	989	3,801	3,041
ईरान	मी.ट.	453	2,761	1,421	7,420	5,936
जापान	मी.ट.	980	840	280	2,160	1,728
संबद्ध देश	मी.ट.	4,522	10,928	3,833	19,824	15,859
चायना पूर्व से ही पाटनरोधी शुल्क	मी.ट.	1,612	5,104	8,867	8,894	7,115
अन्य देश	मी.ट.	140	430	220	223	178
आयात कुल	मी.ट.	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153

			3			
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	15,563	14,804	14,115	15,720	12,576
मांग	मी.ट.	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
सूचीबद्ध मांग		100	143	124	205	164

विभिन्न मापदंडों की तुलना में आयात:

56. यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात में भारत में समान उत्पाद के उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इसमें भारत में घरेलू बिक्री की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
निम्नलिखित की तुलना में आयात					
कुल आयातों में हिस्सा					
ई यू	%	4.81	4.02	8.85	22.26
इंडोनेशिया	%	44.42	40.49	7.66	13.13
ईरान	%	7.22	16.77	11.00	25.64
जापान	%	15.62	5.10	2.17	7.46
संबद्ध देश		72.07	66.38	29.67	68.50
मांग में हिस्सा					
ई यू	%	1.38	2.12	4.23	14.43
इंडोनेशिया	%	12.76	21.32	3.66	8.51
ईरान	%	2.07	8.83	5.25	16.61
जापान	%	4.49	2.69	1.04	4.84
संबद्ध देश		20.71	34.95	14.18	44.39
भारत में उत्पादन में हिस्सा					
ई यू	%	1.97	4.49	8.37	39.00
इंडोनेशिया	%	18.17	45.22	7.24	23.01
ईरान	%	2.95	18.73	10.40	44.92
जापान	%	6.39	5.70	2.05	13.08
संबद्ध देश		29.48	74.14	28.07	120.01
याचिकाकर्ता की बिक्री में हिस्सा					

ई यू	%	1.94	4.47	8.10	40.99
इंडोनेशिया	%	17.91	45.03	7.01	24.18
ईरान	%	2.91	18.65	10.06	47.20
जापान	%	6.30	5.67	1.98	13.74
संबद्ध देश		29.05	73.82	27.16	126.11

घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा:

57. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
मांग में बाजार हिस्सा	%				
संबद्ध देश	%	20.71	34.95	14.18	44.39
ई यू	%	1.38	2.12	4.23	14.43
इंडोनेशिया	%	12.76	21.32	3.66	8.51
ईरान	%	2.07	8.83	5.25	16.61
जापान	%	4.49	2.69	1.04	4.84
अन्य देश	%	8.02	17.70	33.61	20.41
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	71.27	47.35	52.21	35.20

58. अतः यह पाया गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि में इसमें भारी वृद्धि हुई है । इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव:

कीमत कटौती

59. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती । आयातित उत्पाद के पहुंच मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर सभी रिबेटों और करों को छोड़कर घरेलू बाजार के लिए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के साथ तुलना की गई है । घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया था । घरेलू उद्योग की कीमत

का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया था । संबद्ध देशों की सी आई एफ कीमत का समायोजन आयात पश्चात लागू शुल्क हेतु किया गया था । इस तुलना से यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की भारतीय बाजार में बिक्री घरेलू उद्योग की कीमत से कम कीमत पर की गई थी । अतः यह देखा जाता है कि आयातों से घरेलू कीमत में कटौती हो रही थी ।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
संबद्ध देशों का पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	55,089	54,854	68,602	61,853
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	52,728	59,567	71,937	66,555
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	113	136	126
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	(2,362)	4,713	3,335	4,702
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	(100)	200	141	199
ई यू	रु./मी.ट.	(3,316)	(6,510)	1,134	3,334
सूचीबद्ध		(100)	(196)	34	101
ईरान	रु./मी.ट.	3,219	5,396	11,179	9,099
सूचीबद्ध		100	168	347	283
इंडोनेशिया	रु./मी.ट.	(3,287)	5,578	(3,479)	703
सूचीबद्ध		(100)	170	(106)	21
जापान	रु./मी.ट.	(2,016)	4,448	(3,398)	710
सूचीबद्ध		(100)	221	(169)	35
संबद्ध देशों की कीमत कटौती	%	(4.48)	7.91	4.64	7.06
संबद्ध देशों की कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	नकरात्मक	5-15	0-10	0-10
ई यू		(6.29)	(10.93)	1.58	5.00
कीमत कटौती	% रेंज	नकरात्मक	नकरात्मक	0-10	0-10
ईरान		6.10	9.06	15.54	11.30
कीमत कटौती	% रेंज	0-10	5-15	10-20	5-15
इंडोनेशिया		(6.23)	9.36	(4.84)	4.17
कीमत कटौती	% रेंज	नकरात्मक	5-15	नकरात्मक	0-10
जापान		(3.82)	7.47	(4.72)	3.01
कीमत कटौती	% रेंज	नकरात्मक	5-15	नकरात्मक	0-10

कम कीमत पर बिक्री:

60. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, की भी जांच की है । विधिवत जांच के बाद यह नोट किया जाता है

कि संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से काफी कम है ।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
क्षतिरहित कीमत	रु./मी.ट.	***
पहुंच मूल्य		
संबद्ध देश	रु./मी.ट.	61,853
ई यू	रु./मी.ट.	63,220
ईरान	रु./मी.ट.	57,455
इंडोनेशिया	रु./मी.ट.	65,851
जापान	रु./मी.ट.	65,845
कम कीमत पर बिक्री		
संबद्ध देश	रु./मी.ट.	***
ई यू	रु./मी.ट.	***
ईरान	रु./मी.ट.	***
इंडोनेशिया	रु./मी.ट.	***
जापान	रु./मी.ट.	***
कम कीमत पर बिक्री		
संबद्ध देश - रैंज	%	15-25
ई यू	%	10-20
ईरान	%	25-35
इंडोनेशिया	%	5-15
जापान	%	5-15

कीमत हास

61. यह नोट किया जाता है कि कीमत हास के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बनाने और बेचने की लागत तथा बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है। परंतु बनाने और बेचने की लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से काफी अधिक है जिससे कीमत हास हुआ है। कीमत हास काफी अधिक माना गया है।

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
पहुंच कीमत - संबद्ध देश	रु./मी.ट.	55,089	54,854	68,602	61,853
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	100	125	112
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	111	153	150
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	****	****	****	****

सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	113	136	126
----------	-----------	-----	-----	-----	-----

62. अतः सूचना से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू बाजार में कीमत कटौती हो रही थी और पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में हास हुआ था अथवा होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई थी जो अन्यथा काफी उच्च स्तर तक बढ़ गई होती ।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

63. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है ।

(i) उत्पादन:

64. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में 64% की वृद्धि हुई है ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.ट.	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
उत्पादन	मी.ट.	15,335	14,741	13,655	16,519	13,215
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	89	86	86
मांग	मी.ट.	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	143	124	164	164

(ii) क्षमता और क्षमता उपयोग:

65. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान कंपनी की स्थापित क्षमता समान रही है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए अनन्य रूप से

उत्पादन क्षमताओं का उपयोग किया जा रहा है । जहां क्षति अवधि में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं उत्पादन में गिरावट से क्षमता उपयोग में कमी आई है । अतः जहां उत्पाद की मांग में लगभग 64% की वृद्धि हुई है वहीं क्षमता उपयोग में 14% की गिरावट आई ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. ट.	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
उत्पादन	मी. ट.	15,335	14,741	13,655	16,519	13,215
क्षमता उपयोग	%	102.23	98.27	91.03	88.10	88.10
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	89	86	86
मांग	मी. ट.	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	124	164	164

घरेलू बिक्री:

66. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू बिक्री	मी. ट.	15,543	14,804	14,115	15,720	12,576
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	81	81
मांग	मी. ट.	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
मांग में % बिक्री	%	71.18	47.35	52.21	35.20	35.20

(iv) लाभप्रदता:

67. घरेलू समान उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच केवल घरेलू बिक्री के बारे में की गई है । यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु हेतु घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वस्तुतः यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि की शुरुआत के दौरान घरेलू उद्योग लाभ की स्थिति से जांच अवधि में घाटे की स्थिति में पहुंच गया है ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.ट.	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	111	153	150
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	113	136	126
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	124	34	(25)

कर तथा ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	108	44	(9)

68. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति के बावजूद कंपनी ने अत्यधिक तथा रिकॉर्ड लाभ कमाया है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। अतः अत्यधिक या रिकॉर्ड लाभ के बारे में हितबद्ध पक्षकारों का तर्क गलत है।

69. यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग ने यूरिया की लागत को बढ़ाने के लिए लागत समायोजन कर घाटे का दावा किया है। यह नोट किया जाता है कि यही पद्धति समूची क्षति अवधि हेतु लाभ के निर्धारण के लिए अपनाई गई है। अतः लाभ में गिरावट यूरिया की लागत में किसी संभावित वृद्धि के कारण नहीं आई है।

70. यह तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उपयोगिता खपत में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण उपयोगिताओं की ईष्टतम खपत पर विचार करते हुए किया गया है। यह नोट किया जाता है कि उपयोगिताओं की उच्चतर खपत में से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समायोजन करने के बाद भी लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।

(v) रोजगार और मजदूरी:

71. घरेलू उद्योग के पास रोजगार और प्रदत्त मजदूरी निम्नानुसार रही थी :

उत्पादकता	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
रोजगार	सं.	62	68	66	62	62
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	110	106	100	100
मजदूरी	लाख रुपए	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	109	130	121	121

72. यह नोट किया जाता है कि रोजगार में समूची क्षति अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है।

(vi) उत्पादकता:

73. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नानुसार थी :

उत्पादकता	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
प्रति दिवस लाभप्रदता	मी.ट.	44	42	39	38
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	247	217	207	213

74. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता लगभग समान रही थी ।

(vii) निवेश पर आय और नकद प्रवाह:

75. निवेश पर आय का निर्धारण ब्याज पूर्व लाभ तथा उत्पाद में लगाई गई पूंजी पर विचार करते हुए किया गया है । नकद प्रवाह पर प्रभाव का निर्धारण मूल्यहास से पूर्व लाभ परंतु ब्याज लागत के बाद की स्थिति पर विचार करते हुए किया गया है । यह नोट किया जाता है कि 2007-08 में लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में वृद्धि हुई है और उसके बाद क्षति अवधि में उनमें भारी गिरावट आई है । यह भी नोट किया जाता है कि लाभ तथा लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन वही रहा है और उस पर क्षति अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
आर ओ सी ई	%	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	120	65	(13)	(13)
नकद लाभ	लाख रुपए	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	113	52	15	15

(viii) मालसूची:

76. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई है ।

स्टॉक (मात्रा)	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिकीकृत
अथ	मी.ट.	763	538	476	16	13

इति	मी.ट.	538	476	16	815	652
औसत	मी.ट.	651	507	246	416	332
बिक्री	मी.ट.	15,543	14,804	14,115	15,720	12,576
घरेलू बिक्री दिवसों की संख्या के समतुल्य मालसूची	सं.	15	12	6	10	10

(ix) वृद्धि:

77. विभिन्न मापदंडों में वृद्धि के बारे में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है। यह देखा जाता है कि मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के बारे में वृद्धि नकारात्मक है।

वृद्धि	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
उत्पादन में	%		(3.87)	(7.37)	(3.22)
घरेलू बिक्री में	%		(4.75)	(4.65)	(10.91)
क्षमता उपयोग में	%		(3.87)	(7.37)	(3.22)
बिक्री लागत में रु./मी.ट.	%		***	***	***
बिक्री कीमत में रु./मी.ट.	%		***	***	***
लाभ में /लाभ/हानि रु./मी.ट.	%		***	***	***
लाभ/हानि में लाख रुपए	%		***	***	***
पी बी टी में लाख रुपए	%		***	***	***
पी बी आई टी में लाख रुपए	%		***	***	***
आर ओ आई में %	%		***	***	***

(x) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता:

78. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उसने 7,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की योजना बनाई है जो कई उत्पादों के लिए है। इसमें मेलामाइन के लिए क्षमता में अत्यधिक विस्तार शामिल है। कंपनी ने यह तर्क दिया है कि उसकी मंशा मेलामाइन की क्षमता में 40,000 मी.ट. की वृद्धि करने की है। इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट से यह पता चलता है कि *** रुपए प्रति मी.ट. से कम कीमत पर (उक्त अवधि में प्रचलित निविष्टि की कीमत पर विचार करते हुए) निवेश अव्यवहार्य है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मेलामाइन के सतत पाटन के कारण उत्पाद के बारे में कंपनी की विस्तार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के सतत पाटन और उत्पाद में हो रहे वित्तीय घाटे से पूंजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लाजिमी है। यद्यपि, घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है तथापि, घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर इस उत्पाद के कारण पड़े प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तु के लिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

(x) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन:

79. संबद्ध देशों के बारे में उपर्युक्त निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक और न्यूनतम सीमा से ज्यादा है।

छ. कारणात्मक संबंध

80. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमों में सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। निम्नानुसार पाया गया था :

(i) तीसरे देशों से आयात:

81. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के सौदेवार आयात आंकड़े एकत्र किए हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात या लो उच्चतर कीमत पर किए गए हैं या फिर आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से कम है या उस देश पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू है।

(ii) मांग में कमी:

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में अत्यधिक सुधार हुआ है। मांग में संभावित कमी से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

(iii) खपत की पद्धति में परिवर्तन

83. विचाराधीन उत्पाद के बारे में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही इस बारे में कोई बेवजह आरोप लगाया गया है। अब तक की जांच से वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी उत्पादों और ऐसे वैकल्पिक उत्पादों के कारण संभावित क्षति की मौजूदगी का पता चला है।

(iv) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा:

84. यह नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और इनका समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों और उनके बीच प्रतिस्पर्धा का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(v) प्रौद्योगिकी में विकास:

85. प्रौद्योगिकी विकास का कोई आरोप नहीं है और न ही अब तक की जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग को संभावित क्षति प्रौद्योगिकी विकास के कारण हो सकती है।

(vi) निर्यात निष्पादन:

86. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2006-07 के अलावा क्षति अवधि में कोई निर्यात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालन और घरेलू लाभप्रदता पर विचार किया है।

(vii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता:

87. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। उत्पादकता में किसी संभावित गिरावट के लिए घरेलू उद्योग हेतु पुष्टिकृत क्षति के लिए कारण नहीं माना जा सकता है।

पाटन मार्जिन का स्तर और क्षति मार्जिन:

88. प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों पर विचार करते हुए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है और बाद में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के बारे में खरीदी गई निविष्ट का सत्यापन किया है।

89. यथानिर्धारित पाटन मार्जिन का स्तर और क्षति मार्जिन का उल्लेख नीचे किया गया है अतः अनुरोध किया जाता है कि ये स्तर अत्यधिक माने गए हैं।

	इकाई	ई यू	ईरान	इंडोनेशिया	जापान
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज %	25-35	25-35	20-30	40-50
एनआईपी	रू.मी.ट.	***	***	***	***
परिवर्तित दर	रू./अम.डॉ.	47.88	47.88	47.88	47.88
एन आई पी	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	1,320	1,200	1,375	1,375
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज %	10-20	25-35	5-15	5-15

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

90. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की कुल मांग में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में भी भारी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही थी। यह भी निर्धारित किया जाता है कि पाटित आयातों का कीमत कटौती, कीमत हास और कम कीमत पर बिक्री के संबंध में अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जो काफी अधिक माना गया है।

91. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों का कीमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है जिससे लाभ और निवेश पर आय में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग जांच अवधि में घाटा उठा रहा है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण अधिक हुई है।

92. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः "पाटन" की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली "क्षति" को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली तथा उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपायों के लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयातों में किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचेगी तथा इसलिए उपभोक्ताओं हेतु उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
94. इस बात को स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण से सम्बद्ध वस्तुओं के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण उस राशि तक प्रतिबंधित रखा जाए जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निवारण हेतु आवश्यक है । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी ।

ञ. सिफारिशें

95. हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण हुई है ।

(ग) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था । निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था कि वे पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के पहलुओं

के विषय में सूचना उपलब्ध करवाएं । पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं तथा कारणात्मक संबंधों के बारे में जांच करने तथा संपन्न करने; एवं सकारात्मक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को को हुई वास्तविक क्षति निर्धारित करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए शुल्क लागू किया जाना अपेक्षित है । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पादों के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है ।

97. शुल्क संरचना के बारे में मामले के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि तथा पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क के बैचमार्क/संदर्भ स्वरूप की सिफारिश करना उचित समझा जाता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्याति संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लागू किया जाएगा ।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29336100	मेलामाइन	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
2	वही	वही	यूरोपीय संघ	ई यू से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
3	वही	वही	ई यू से इतर अन्य कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
4	वही	वही	ईरान	ईरान	कोई	कोई	1446	मी.ट.	अम.डॉ.
5	वही	वही	ईरान	ईरान से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1446	मी.ट.	अम.डॉ.
6	वही	वही	ईरान से इतर अन्य कोई देश	ईरान	कोई	कोई	1446	मी.ट.	अम.डॉ.
7	वही	वही	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
8	वही	वही	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
9	वही	वही	इंडोनेशिया से इतर अन्य कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
10	वही	वही	जापान	जापान	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
11	वही	वही	जापान	जापान से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.

12	वही	वही	जापान से इतर अन्य कोई देश	जापान	कोई	कोई	1537	मी.ट.	अम.डॉ.
----	-----	-----	------------------------------	-------	-----	-----	------	-------	--------

98. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल होंगे।

99. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

Final Findings

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Melamine originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan—Final findings.

Background:

No. 14/35/2010-DGAD.—Whereas the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules) received an application from M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., (GSFC) Vadodara through M/s. TPM Solicitors & Consultants, New Delhi (hereinafter referred to as the Applicant) alleging dumping of Melamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from EU, Iran, Indonesia & Japan (hereinafter referred to as subject countries) and requested for the initiation of Anti-dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. And whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, after examination of the same with regard to adequacy and accuracy, issued a Public Notice dated 7th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in accordance with the Rule 6 (1) of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of Anti Dumping Duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
3. And whereas, the M/s Century Plyboards (I) Ltd. filed a writ petition before Hon'ble Calcutta High Court, challenging a notification dated 7th December, 2010. The single bench of High Court in its judgment dated 19.08.2011 stated as follows:

“Mr. Bose argued that the Designated Authority had the discretion not to exclude an importer in view of use of the expression “may” in Rule 2(b). However, it is clear from

Rule 2(b), as amended by D.R. Notification NO.18/2010 Customs (N.T.) dated 27th February, 2010, that importers have been excluded. The use of the expression 'except' is significant. 'Domestic industry' has been defined to mean the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like articles and any activity connected therewith, whose collective output of the said article constitutes a major portion of the domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof. Where producers are related to exporters or importers or are themselves importers, the term domestic industry might be construed as referring to the rest of the producers only.

As argued by Mr. Bose, 'shall' had been substituted by 'may'. Thus, the principle - 'may' could be construed as 'shall' - would not apply in that the rule maker had very consciously substituted the expression 'may' in place of 'shall'. However, further amendment by the Notification dated 27th February, 2010 leaves no manner of doubt that importers cannot be included in the definition of domestic industry. The Designated Authority may have discretion whether or not to construe 'domestic industry' as referring to the rest of the domestic producers apart from the importer. The initiation of investigation at the instance of Gujarat State Fertilizers, which is admittedly and on the face of the records, an importer, is legally not sustainable. The writ application is, thus, allowed. The impugned notification is set aside."

4. And whereas M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Vadodara filed an appeal against the impugned order dated 19.08.2011. Subsequently, Govt. of India filed an appeal against the impugned order. While hearing the appeal, the division bench of Hon'ble Calcutta High Court passed the following order on 21.11.2011.

"The impugned judgment and order shall remain stayed, till the disposal of this appeal as the notification has been quashed. We direct the designated authority to proceed in accordance with law with regard to the enquiry and investigation as prescribed in the rules; however, no report may be submitted. If the report is against Dr' Chakraborty's clients, no action need be taken without the leave of this Court. The views we have expressed while passing the aforesaid order, gets support from a Supreme Court decision rendered in the case of Association of Synthetic Fibre Industry -vs- J.K. Industries Ltd' and Ors., reported in (2005) 11 SCC page 482."

5. And whereas by the order dated 7th May 2012, the division bench has granted liberty to present a report with the government but the government shall not take any action thereto till the disposal of the appeal.

Procedure:

6. The procedure described below has been followed:
 - i. The Authority notified to the Embassy/Trade Representative of subject countries in India about the receipt of application alleging dumping of subject goods made by the Applicant before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

- ii. The Authority sent copies of Initiation Notification dated 7th December, 2010 to the Embassy/Trade Representative of the subject countries in India informing about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6 with a request to advise the exporters/ producers of the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters/producers and Non-Confidential Version of the application was also sent to them, along with the names and addresses of the known exporters from the subject countries as per the addresses made available by the applicant.
- iii. The Authority sent copies of Initiation Notification dated 7th December, 2010 along with non-confidential version of application as well as exporter's questionnaire to the known producers/exporters of the subject countries as per the addresses made available by the applicant and requested them to provide relevant information and make their views known in writing within 40(forty) days of Initiation Notification.
- iv. The Authority sent copies of Initiation Notification dated 7th December, 2010 along with importer's questionnaire to the known importers and domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to provide relevant information and make their views known in writing within 40(forty) days of Initiation Notification.
- v. The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4):
 - a. Pt.DSM Kaltim Melamine, Indonesia
 - b. DSM Melamine, EU
 - c. DSM Melamine, Indonesia
 - d. Agrolinz Melamine International GmbH, EU
 - e. Nissan Chemicals Industries Ltd., Japan
 - f. Khorasan Petrochemical Company, Iran
 - g. Iran Petrochemical Commercial Co., Iran
- vi. Following exporters/producers from the subject countries have responded to the initiation but have not filed any questionnaire response.
 - a. Ministry of Trade on the Republic of Korea
 - b. PT OCI Kaltim Melamine, Indonesia
- vii. A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4).
 - a. Greenply Industries Ltd.
 - b. Merino Industries Ltd.
 - c. Merino Panel Products Ltd.
 - d. Golden Laminates Ltd
 - e. Surya Vikas Plywood Pvt. Ltd.
 - f. Katyani Chemtech India Ltd.
 - g. Rushil Décor Ltd.
 - h. Sundek India Ltd.
 - i. Bloom Dekor Ltd.

- j. HEF India Private Ltd.
- k. Century Plyboards India Ltd.
- l. Managlam Timber Products Ltd.
- m. Virgo Industries
- n. Alfa Ica Ltd.
- o. The Bombay Burmah Trading Co.

viii. Following importers/interested parties have responded to the initiation.

- a. Eximcorp India Pvt Ltd
- b. Century Plyboard (I) Ltd
- c. Indian Laminates Manufacturers Association, Ahmedabad

ix. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods made in India during the past three years and the period of investigation. The information received from DGCI&S was analyzed and the same was compared with the information received from the IBIS (secondary sources). After the detailed examination, it was decided to take into account the information from IBIS as it had reported higher volumes.

x. M/s Century Plyboards (I) Ltd. filed a writ petition before Hon'ble Calcutta High Court, challenging a notification dated 7th December, 2010. The single bench of High Court in its judgment dated 19.08.2011 stated as follows:

"Mr. Bose argued that the Designated Authority had the discretion not to exclude an importer in view of use of the expression 'may' in Rule 2(b). However, it is clear from Rule 2(b), as amended by D.R. Notification NO.18/2010 Customs (N.T.) dated 27th February, 2010, that importers have been excluded. The use of the expression 'except' is significant. 'Domestic industry' has been defined to mean the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like articles and any activity connected therewith, whose collective output of the said article constitutes a major portion of the domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof. Where producers are related to exporters or importers or are themselves importers, the term domestic industry might be construed as referring to the rest of the producers only.

As argued by Mr. Bose, 'shall' had been substituted by 'may'. Thus, the principle - 'may' could be construed as 'shall' - would not apply in that the rule maker had very consciously substituted the expression 'may' in place of 'shall'. However, further amendment by the Notification dated 27th February, 2010 leaves no manner of doubt that importers cannot be included in the definition of domestic industry. The Designated Authority may have discretion whether or not to construe 'domestic industry' as referring to the rest of the domestic producers apart from the importer.

The initiation of investigation at the instance of Gujarat State Fertilizers, which is admittedly and on the face of the records, an importer, is legally not sustainable.

The writ application is, thus, allowed. The impugned notification is set aside."

- xi. And whereas M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Vadodara filed an appeal against the impugned order dated 19.08.2011. Subsequently, Govt. of India filed an appeal against the impugned order. While hearing the appeal, the division bench of Hon'ble Calcutta High Court passed the following order on 21.11.2011.

"The impugned judgment and order shall remain stayed, till the disposal of this appeal as the notification has been quashed. We direct the designated authority to proceed in accordance with law with regard to the enquiry and investigation as prescribed in the rules; however, no report may be submitted. If the report is against Dr' Chakraborty's clients, no action need be taken without the leave of this Court. The views we have expressed while passing the aforesaid order, gets support from a Supreme Court decision rendered in the case of Association of Synthetic Fibre Industry -vs- J.K. Industries Ltd' and Ors., reported in (2005) 11 SCC page 482."

- xii. And whereas by the order dated 7th May 2012, the division bench has been granted liberty to present a report with the government but the government shall not take any action thereto till the disposal of the appeal
- xiii. In pursuant to the order of the division bench of Hon'ble Calcutta High Court the Authority proceeded with the investigation as per the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time.
- xiv. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, as requested.
- xv. The Authority verified the information furnished by the Domestic Industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping Duty lower than the Dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a Oral Hearing held on 6th March, 2012. The interested parties who presented their views in the Public Hearing were requested to

- file their written submissions of the views expressed orally and rejoinder to the submissions filed by other interested parties.
- xvii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April-09 to 30th June-10 (15 months). The examination of the trends in the context of injury analysis covers the period from 2006-07, 2007-08, 2008-09 and Period of investigation.
- xviii. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant investigation were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement, to the extent considered relevant, have been duly considered in these findings. The following interested parties have submitted their comments pursuant to issuance of disclosure statement:
- (a) M/s GSFC, Vadodara
 - (b) M/s Century Ply (I) Limited, Kolkata
 - (c) M/s Eximcorp India Pvt. Ltd.
 - (d) M/s Indian Laminate Manufactures Associates (ILMA)
- xix. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential summaries of the information filed on confidential basis.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the findings on the basis of the 'facts available'.
- xxi. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rules.

Product under consideration and like article:

7. The product under consideration in the present petition is Melamine, a tasteless, odorless, and non-toxic substance. Melamine formaldehyde resin is used for laminates as it offers good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties. Asbestos filled Melamine resins possess very high dielectric strength and high resistance. Beside the best dimensional stability, Melamine Formaldehyde moulding powder gives clear and bright colors, easily moldable and offers resistance to surface scratching. Melamine is

reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products.

8. The subject goods is classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act at subheading no. 29336100. The customs classification is however for reference purpose only and will have no binding on the scope of the present investigation.

Views of the interested parties:

9. None of the interested parties made any submissions regarding the product under consideration at any stage of the proceedings.

Like Article:

10. With regard to like article, Rule 2(d) provides as under:

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

11. The applicant has claimed that there is no known difference in the product under consideration produced and exported from subject countries and subject goods produced by the domestic industry. It is noted that the subject goods produced by the Indian industry and those imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
12. The Authority notes that none of the interested parties have raised any argument in relation to product under consideration and like article. The Authority after due consideration and examination of the submissions made by the interested parties notes that the subject goods produced by the petitioner company are like articles to the product under consideration imported from subject countries in accordance with the Anti-Dumping Rules.

Domestic Industry and Standing:

Views of the domestic industry

13. The following are the views of the domestic industry:
 - a. At the time of initiation, clear understanding even with the Designated Authority was that the Designated Authority has discretion under the law. Therefore the petitioner, while submitting the information, did not analyze the situation carefully.

- b. Petitioner has merely facilitated the imports – The petitioner has ordered the goods from the exporter and sold the same via high sea agreements/ex-bond
- c. The petitioner has not filed any bill of entry for clearance of the goods for home consumption. Petitioner has facilitated these imports and filed bill of lading and bill of entry for warehousing. Bill of entries for home consumption have been filed directly by the consumers/customers of GSFC.
- d. The petitioner has acted as a facilitator so that these customers do not start resorting to direct import of dumped goods and cause long term damage to the domestic industry.
- e. Designated Authority has discretion under Rule 2(b) to decide on merits whether a company who is importing the product under consideration or which is related to an exporter or importer should be included or excluded for the determination of the domestic industry.
- f. GSFC has not sold such material at significant profits. In general, GSFC policy is to sell the material at price comparable to import price. However, there may be small variations in the purchase and sale price in view of exchange fluctuations and such other factors.
- g. GSFC is not resorting to imports in order to benefit from dumping. Thrust of GSFC has not turned to imports. The company's thrust continues to be on own production. The company is in fact expanding its capacities to meet the demand for the product in the Country.
- h. Following the issuance of disclosure statement M/s GSFC has submitted that it should not be considered as the importer for more than one reason. Further they have stated that they have merely facilitated the imports i.e. the petitioner has ordered the goods from the exporter and sold the same via ex bond basis. Further, they have reiterated their comments made to the Authority on earlier occasion and stated that they facilitated the imports of these materials in order to prevent the customers from directly importing the material at the time of production suspension/disruption or against advance licence requirement of the consumers for the reason that these customers do not start resorting to direct import of dumped goods and cause long term damage to the industry.

Views of other interested parties

- 14. The following are the views of other interested parties
 - a. Applicant lacks basic qualifications under the statute to be treated as a domestic industry. No published information and reasons thereof has been provided by the

- applicants regarding the shutdown of plants as claimed by the petitioner as a reason for imports made by them.
- b. Petitioner does not constitute 'domestic industry as they have imported the product under consideration.
 - c. After the issuance of disclosure statement the various interested parties have reiterated their views with regard to the fact that the domestic industry applicant does not constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b). They have also disputed the claims made by M/s GSFC that they are not importer but facilitator of the subject goods imported from subject countries. It has been submitted by various importers and users that this is a case where the subject goods have been imported for a valid consideration upon payment by the applicant to the overseas exporter for the purpose of its sale and stored or warehoused in bond until its sale by the importer applicant in India. It has further been stated that the sales having taking place after warehousing of the cargo on the prevailing market price does not allow the applicant to claim that they were merely a facilitator to such transactions.

Examination of the Authority

15. The petition was filed by M/s Gujarat State Fertilizers and Chemical Ltd (GSFC). Rule 2(b) read as follows at the time of initiation

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

16. Rule 2(b) was amended on 01.12.2011. and now reads as follows.

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

17. At the time of initiation, the petitioner stated that they have made imports at the time of their production disruption to facilitate requirements of its small customers, who wished the petitioner to import the material and supply the same. It was submitted by the petitioner that bill of entry for these imports for customs clearance were not filed

by them. Further during the investigation, the petitioner contended that they are not importers but only have facilitated the imports. During the proceedings, M/s Indian Laminate Manufacturer's Association and Exim Corp India Private Limited and others contended that Applicant lacks basic qualifications under the statute to be treated as a domestic industry. The Authority has examined the submissions made by interested parties and has also carried out onsite verification of records of the domestic industry and on the basis of examination, it is noted that

- a. there was no high sale made by the domestic industry of the subject goods during the subject period. It was noted that M/s GSFC had filed the bill of entries for warehousing purpose to the customs while importing the subject goods from the subject countries. However, it was noted that they did not file the bill of entries for home consumption for the subject goods imported by them and had sold the subject goods made imported by them and sold the same on ex bond basis to various buyers.
 - b. It was noted that M/s GSFC has not paid sales tax on the imported product sold on ex-bond basis. Instead, the eventual importer filing bill of entry for home consumption has paid import taxes, including basic customs duty, CVD, SAD, etc.
 - c. It was further noted that M/s GSFC had sold the subject goods without significant additions for profits. After verifying the records, it was noted that if all expenses associated with imports of subject goods from subject countries for warehousing purpose and its sales on ex bond basis are considered, it is seen that there is a very marginal profit (in some transactions there is a marginal loss also) in these procurements. It is also noted that the procurement price of GSFC is quite comparable to the weighted average import price during the POI.
 - d. It was noted that the imports made by M/s GSFC constituted approx 11.78 % of its production, 7.44% of total imports and 4.57% of consumption in India during the POI.
18. During the investigation proceedings, Hon'ble Chennai High Court in the matter of Nirma Ltd. vs. Saint Gobain Glass India Ltd. has held that the Designated Authority has discretion under Rule 2(b) and the amendment dated 27th Feb., 2010 has not taken away the discretionary power of the Designated Authority.
19. The Authority has examined the matter and it holds that the Petitioner has not filed bill of entries for home consumption. The petitioner has filed bill of entries for warehousing and thereafter the bill of entries for home consumption have been filed directly by the consumers. Even though M/s GSFC had imported and sold the subject goods, the Authority is of the view that the focus of GSFC has not turned to imports and the company is not behaving like an importer trader. The focus of the company continues to be that of a producer and do its own production.
20. Having regard to the definition of Rule 2(b), the facts of the case as mentioned above, the Authority determines that the applicant constitutes domestic Industry within the

meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Other Issues

Views of the domestic industry

21. The following are the views of the domestic industry

- (a) The company uses urea for producing melamine which is not a fertilizer product. Hence, there are the two price mechanism involved in natural gas (a) Administrative Price Mechanism (APM) and (b) Non Administrative price Mechanism (Non APM).
- (b) The Govt. of India provides natural gas to GSFC at its own prices and determines its cost of production for fertilizer purposes on the basis of these prices. The company is not allowed to use this natural gas for production of other products, including melamine. The company must buy it from market for production of such other products, including melamine.
- (c) Therefore the actual cost of production for production and sale of melamine for the company cannot be established unless the price at which the company has purchased natural gas for production of melamine. In a situation where the company has purchased an input at several prices for several purposes, it follows that the weighted average procurement cost of the company is not the cost of input for all such products, particularly when the company has bought the same input at different prices for different products.
- (d) Therefore, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas must be taken for determining cost of ammonia which is required for the production of urea which in turn requires for the production of Melamine. Natural gas made available to the company at pre-determined price for eventual production of fertilizer is wholly irrelevant for the purpose

Views of other interested parties

22. The following are the views of other interested parties

- a) The petroleum feedstock prices in India are significantly higher than major exporting countries. The Indian industry is at disadvantageous position with regard to overhead costs.
- b) Petitioner has not disclosed complete information in the petition as per prescribed format. Following are missing
 - a. Question relating to users of the alleged dumped goods is missing in section I of the application.
 - b. Question 14 in section VI of application is missing, which requires for details of the purchases policy, Sales policy, Stores accounting, inventory/stock/WIP valuation and Quality control procedure.

- c. Question 10 in section VI of application is missing, which is related to return/profit.
- c) Cost of production claimed by domestic industry highly inflated. In sunset review on imports of Melamine from China PR, the Authority considered average price of natural gas after verification. Same approach should be adopted by the Authority in the present case.

Examination of Authority

23. The issues raised by the interested parties have been examined herein below by the Authority considering the legal provisions and practice being adopted by the Authority.
- a. As regards the issue relating to price of natural gas which should be taken for determining cost of ammonia for production of melamine, the Authority notes that during verification at the premise of the domestic industry, the Authority found that the amount of natural gas required by GSFC for production of fertilizers is far more than what it gets under APM scheme from Government. Therefore, the company had to procure natural gas at non APM prices for production of Urea as well. Therefore there is no reason to believe that GSFC is using natural gas made available to the company on APM prices for production of melamine when the volume is not sufficient even for production of fertilizer. Hence, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas alone is relevant for determining cost of ammonia which is required for the production of urea which in turn is required for the production of Melamine
- b. As regards the argument relating to the approach adopted by the Authority in sunset review while determining price of natural gas, it is noted that at the time of sunset review on imports of Melamine from China PR, the law was different. At that point in time, the principle stated in *Reliance Industries vs. Designated Authority* related to non injurious price was the binding law and was given effect by the Designated Authority. The Hon'ble Supreme Court in the stated case held that market price of the inputs should be taken. Hence in light of the decision of Hon'ble Supreme Court, the Authority in the sunset review adopted market price of natural gas for NIP determination. However, in the present case, the law has been modified and Annexure III has been introduced which requires the Authority to determine non injurious price as per principles laid down in this annexure. This requires the Authority to consider the records maintained by the company relating to product under consideration.
- c. As regards the argument that Indian industry is at disadvantageous position with regard to overhead costs, the Authority, after examining the contentions of the interested parties and after verification of the documents notes that the domestic industry has operated in these conditions throughout the injury period. The Authority also notes that the Hon'ble CESTAT held in the matter of *M/s. Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v.*

Designated Authority that question of injury to domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions, but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments.

- d. As regards the argument that Petitioner has not disclosed complete information in the petition as per prescribed format, the Authority notes that an application under the rules should be in the form as may be specified by the designated authority and should be supported by evidence of (a) dumping, (b) injury, where applicable, and (c) where applicable, a causal link between such dumped imports and alleged injury. Further, the rules provide that the Designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application received; unless the Authority examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury, and causal link between such dumped imports and the alleged injury to justify the initiation of an investigation.

Methodology for calculation of dumping margin:

Views of the domestic industry

24. The following are the views of the domestic industry

- a. Efforts were made to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries. However, the petitioner has not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries.
- b. In view of the above, petitioner has taken raw material price of urea as per the import price of subject countries - wherever available. In case of Iran, the export price from Middle-East (Qatar) to Japan has been taken for constructing the normal value of Iran
- c. none of the foreign producers have responded to the authority in the form and manner prescribed
- d. The dumping margin is not only above *de-minimus* but also substantial for all the four countries.

Views of other interested parties

25. The following are the views of other interested parties

- a. petitioner has determined the normal value for the subject countries except Iran on the basis of construction method and raw material prices have been adopted on the basis of actual import price of Urea during calendar year 2009 (12 Months) and not on the basis of import price prevailed during period of investigation.
- b. Except for Iran, all producers in the subject countries are public companies whose accounts are published, which could have been used to determine normal value.

Normal Value of subject countries

26. It is noted that no producer or exporter of subject goods from subject countries have filed response to the exporters questionnaire in the subject investigation. In fact, no estimates for the normal value or evidence have been placed on record by any interested parties (with the exception of domestic industry) to the Authority. Therefore under the Anti-dumping rules, the Normal value in respect of subject goods from EU, Iran, Indonesia & Japan needs to be constructed.

27. The normal value for the Melamine from subject countries has been constructed based on the following principles.

- (a) Based on WTA import data in respect of imports from world, the international prices for Urea have been considered. In the case of Iran, the international price of urea is not available in the WTA. Hence, the export price from Iran to India has been adopted after suitable adjustment. The best utilisation norm of the raw materials based on the best information available has been considered.
- (b) Cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest have been considered on the basis of best information available.
- (c) 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

28 The CNV computed on the above basis is as follows:

Country	Normal value Rs /MT	Normal value US\$/MT
EU	***	***
Iran	***	***
Indonesia	***	***
Japan	***	***

Export price of subject countries

29. None of the exporters/producers in the subject countries have responded to the Authority in the form and manner specified. In view of non-cooperation from the concerned exporters, the export price has been determined on the basis of Indian customs data. The data reported by the IBIS for imports from subject countries has been relied upon to determine CIF export price. Adjustment on best information available, on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges, have been made to arrive at the ex-factory export price. By adopting the above method, the net export price has been calculated as mentioned in the table below.

Country	Net Export Price Rs /MT	Net Export Price US\$/MT
EU	54,124	1,130

Iran	50,640	1,058
Indonesia	57,198	1,195
Japan	57,401	1,199

Determination of dumping margin:

30. Considering the Normal value and the Export price as determined above, the dumping margin works out as follows:

	unit	EU	Iran	Indonesia	Japan
Normal value	US \$/MT	***	***	***	***
Net export price	US \$/MT	1,130	1,195	1,058	1,199
Dumping margin	US \$/MT	***	***	***	***
Dumping margin	Range %	25-35	25-35	20-30	20-30

31. The Authority notes that the dumping margin from each of the subject countries is more than the de-minimis limits prescribed.

Examination of Injury and Causal Link:

32. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "taking into account all relevant facts, including the volume of the dumped imports, their effect on prices in the domestic market for the like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports are otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Views of the Domestic Industry:

33. The following are the views of the domestic industry

- a. Almost 15 months have passed since the initiation of investigation and therefore adequate opportunity has been provided to the opposing parties since the initiation of investigation to file the relevant information. Hence requesting for more time for filing of the submissions on the part of the opposing party at this late stage, is

nothing but malafide intention on the part of the opposing party to delay the investigation.

- b. ILMA's total estimated size of Rs. 3300 Crores, no industry can be a small industry. Further,
- c. The margins of dumping for subject goods from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;
- d. The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;
- e. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market.
- f. The products manufactured by the producers from the subject countries inter-se and in comparison to the products manufactured by petitioner have comparable properties. In other words, goods supplied by subject countries and by the domestic industry are like articles.
- g. There are limited parties who use this material. Imported and domestic materials are being used interchangeably by same segment of the customers.
- h. The exporters from the subject countries and petitioner have sold the same product in the same periods to the same segment of customers.
- i. Market share of imports from each of the subject countries is more than de minimus.
- j. Domestic producer and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both are being used by the consumers interchangeably.
- k. The company uses urea for producing melamine which is not a fertilizer product. Hence there are the two price mechanism involved in natural gas (a) Administrative Price Mechanism (APM) and (b) Non Administrative price Mechanism (Non APM).
- l. The Govt. of India provides natural gas to GSFC at its own prices and determines its cost of production for fertilizer purposes on the basis of these prices. The company is not allowed to use this natural gas for production of other products, including melamine. The company must buy melamine from market for production of such other products, including melamine.
- m. Therefore the actual cost of production for production and sale of melamine for the company cannot be established unless the price at which the company has purchased natural gas for production of melamine. In a situation where the company has purchased an input at several prices for several purposes, it follows that the weighted average procurement cost of the company is not the cost of input for all such products, particularly when the company has bought the same input at different prices for different products.
- n. Therefore, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas must be taken for determining cost of ammonia which is required for the production

of urea which in turn requires for the production of Melamine. Natural gas made available to the company at pre-determined price for eventual production of fertilizer is wholly irrelevant for the purpose.

- o. Demand of the product in the Country shows a positive growth throughout the injury period with a slight decline in the year 2008-09.
- p. Imports from subject countries have increased significantly in the period of investigation.
- q. the imports have increased in absolute terms;
- r. the share of imports from subject countries has increased in relation to demand in India. Also, the share of domestic industry has declined.
- s. the imports have increased in relation to production in India.
- t. the landed price of imports were substantially lower than the domestic selling prices in POI.
- u. that imports are undercutting the domestic industry prices. As a result of this price undercutting, the imports are suppressing the prices in the domestic market in India
- v. Production and consequently capacity utilization of the domestic industry has started declining from 2007-08. Production and Sales of the domestic industry should have increased with the pace of increase in demand of product in India but has significantly declined in the period of investigation. The dumped imports have taken a large share in demand by undercutting the domestic prices. Dumped imports have not only prevented the Domestic industry to adequately utilize its production capacities, but have forced the domestic industry to reduce its utilization at lowest level ever during the period of investigation. The dumping has thus caused significant volume injury to the domestic industry.
- w. Sales volumes of the domestic industry have declined over the injury period. Further, the sales volume has declined by 20% from the base year in the period of investigation.
- x. With the movements in urea price, the domestic industry reduced or increased its prices. After 2007-08, cost of production of the domestic industry increased significantly. The petitioner however could not increase its selling prices at the same rate due to presence of dumped imports at much lower prices from subject countries. Consequently, profitability of the domestic industry improved in 2007-08, but deteriorated thereafter significantly.
- y. ROI and cash flow have shown the same trend as that of profits
- z. Market share of the domestic industry has severely declined whereas that of imports has significantly increased due to low priced imports in period of investigation
- aa. Inventories with the domestic industry have increased significantly during period of investigation.
- bb. There is negative growth in sales volumes, production, capacity utilization over the injury period whereas cost of sales, selling price, profitability, etc. shows positive

growth till 2008-09 and became negative in 2008-09 and period of investigation due to dumped imports

cc. the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

dd. the petitioners have filed copy of different letters from Ministry of Chemicals & Fertilizers stating as follows:

- a. the cheapest source of input must be used for restricting subsidy.
- b. therein production plan of the company (for arranging and regulating natural gas). Any excess production of urea by the company for purposes other than fertilizers is not entitled for any subsidy or concessional rates.
- c. laying down therein energy consumption norms for production of fertilizers, beyond which no subsidy is available to the unit.
- d. in case of multi product companies, APM gas is to be allowed only for subsidized fertilizer activities
- e. APM gas used by such units as ours for manufacturing of products other than fertilizers should be charged at market price
- f. APM gas would be supplied to only the power and fertilizers section.

Views of domestic industry after issuance of disclosure statement

34. The following are the views of domestic industry on the issue of dumping, injury and causal link:

(i) The domestic industry has reiterated its submissions made by it on earlier occasions to the authority. In particular, they have stated that production of Melamine requires Urea as a major input. Urea is produced using ammonia as one of the inputs. In turn, natural gas is required for production of Ammonia. GSFC is obliged to sell fertilizer at a price determined by the Govt. of India. The difference between the cost of production of fertilizers and selling price fixed by the Govt. of India is paid by the Govt. of India. The Govt. of India has labeled this as subsidy, even though it is nothing but difference between the price that the company should charge from the market and the price at which the company has billed the product. This "subsidy" is provided by Govt. of India on natural gas for the fertilizer purposes only. The company uses urea for producing melamine which is not a fertilizer product. Hence there are the two price mechanism involved in natural gas (a) Administrative Price Mechanism (APM) and (b) Non Administrative price Mechanism (Non APM). The Govt. of India provides natural gas to GSFC at its own prices and determines its cost of production for fertilizer purposes on the basis of these prices. The company is not allowed to use this natural gas for production of other products, including melamine. The company must buy melamine from market for production of such other products, including melamine. Therefore the actual cost of production for production and sale of melamine for the company cannot be established unless the price at which the company has purchased natural gas for production of melamine. In a situation where the company has purchased an input at several prices for several purposes, it follows that the weighted average procurement

cost of the company is not the cost of input for all such products, particularly when the company has bought the same input at different prices for different products. Therefore, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas must be taken for determining cost of ammonia which is required for the production of urea which in turn requires for the production of Melamine. Natural gas made available to the company at pre-determined price for eventual production of fertilizer is wholly irrelevant for the purpose.

(ii) It has been submitted that the consumption price of urea for the domestic industry is in fact comparable (or, even lower) than the price of urea prevailing in some of the subject countries. Thus, it is not a situation where the urea consumption price of the petitioner domestic industry is higher. Such being the case, there is no basis for the argument that the company's average consumption price of natural gas (which represents consumption in product under consideration as also products not under consideration) should be adopted for the present purposes.

(iii) It has been further submitted that there is no basis for the argument that the costs determined by the company are not on the basis of records maintained by the company. The costs are in fact on the basis of records maintained by the company. However, when the company is producing several products for which it is buying and consuming several inputs, the Designated Authority is required to consider the cost and price of the product under consideration. The Designated Authority cannot consider costs and prices of other products produced by the company. Similarly, the Designated Authority is required to consider profit in the product under consideration. Profit of the company or its unit or division is entirely irrelevant.

(iv) It has been submitted that the anti dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/kg. in order to serve the purpose for which anti dumping duties are imposed. This is required as the prices of natural gas and resultantly urea have increased very significantly after the investigation period. The price of natural gas at present is Rs. 17 per sm³, while the same was Rs. 11.87 per sm³ during the investigation period. Thus, on this account alone, the cost of production has increased by Rs. 8200 pmt. Such being the case, any other form of duty (except fixed or ad-valorem) would imply ineffective form of duty and continued dumping and consequent injury to the domestic industry. Natural gas prices are expected to increase further. Further, the appreciation of US\$ has direct impact on the cost of production

Views of the Exporters, Importers and other interested parties:

35. The following are the views of other interested parties

- a. Non injurious price has been constructed on data without any nexus to actual incidence but on hypothesis. The weighted average cost of urea the key input minus subsidies received be taken into account to construct the cost.
- b. The applicant despite such rising trends of raw material has generated sufficient and record profits.

- c. Domestic industry is unable to meet the demand in India and there is wide demand supply gap. Imports are made to fill the gap.
- d. No injury has been caused to the petitioner. There is no price suppression or depression effect.
- e. Non-confidential petition is not replica of the confidential petition. The initiation notification states that bill of entry for these imports for customs clearance were not filed by them.
- f. Cost of production claimed by DI highly inflated. In Sunset review on imports of Melamine from China PR, the Authority considered average price of natural gas after verification. Same approach should be adopted by the Authority in the present case.
- g. There is an increase in utilities consumption per unit of production and such increase in utilities cost cannot and should not be attributed to alleged dumping
- h. Petitioner cannot cater to the demand of the subject product in India due to capacity constraints.
- i. There is no Material Injury to the Domestic Industry
- j. No reasons as to why production-disruption has not caused injury to the domestic industry during POI. Further, utilities consumption i.e. power, steam has been significantly increased during POI as compared to base year
- k. If any imports are made under duty exemption scheme, same should be excluded from total imports
- l. Cost of the input of urea should be those adopted in the financial statement of the company in terms of closing value of stocks over the period concerned.
- m. No attempts were made to procure the prices prevailing in the Indonesian market which is an open and transparent market to work out dumping
- n. As per the annual reports, petitioner's net sales including subject goods have increased and generated healthy profits. Any slowdown in 2010 is because of the economy meltdown as stated in the annual reports.
- o. The company is operating at 92% capacity utilization and stocks declined to minimum levels and there are only few industries who could achieve such high levels.
- p. Any loss is due to the cost adjustments made to inflate the cost of upstream urea feedstock rather than the claimed price effect.
- q. Cost of sales trend is not reflective of the fluctuation in the international urea prices. Prices from Indonesia are closer to the fluctuation in the feedstock than domestic industry. The market of melamine is not supportive of the companies who do not follow the cost trend of urea.
- r. Reduction in market share is due to increase in consumption and inability of domestic industry to meet the increased demand.

- s. The cost of domestic industry is well above the trend of the decline in the urea price and these accounts for the purported loss of profitability.
- t. No causal link has been established.
- u. Injury during period of investigation is because of the faulty sales policy adopted by the petitioner. If the petitioner would follow the international prices, there would be no injury.
- v. The rising prices of the product under consideration per se are not a ground for seeking relief under AD law.
- w. There is no justification for POI which is more than 12 months period.

Views of various interested parties i.e exporters, importers and users and association after issuance of disclosure statement

36. **The following are the views of other interested parties on the issue of dumping, injury and causal link:**

(i) There is no injury to the applicant based on the Annual report and also from the fact that net sales realization (NSR) is higher than the highest possible NIP. The NSR is also higher than the cost of production. In such a situation, there cannot be any injury leave alone material injury to the domestic industry. Therefore, authority has made a grave error in the analysis of injury data submitted by the applicant. It has been submitted that the authority should revisit the injury determination in view of gross errors committed in the computation.

(ii) On the issue of other injury parameters submitted by the petitioner and analysed by the Authority, there is no injury to the domestic industry.

(iii) The normal value constructed by the authority should be divulged along with its principles.

(iv) On the issue of determination of non-injurious price to the domestic industry. It has been submitted that details of the computation of the same should be divulged by the authority. In particular they have requested the authority to disclose whether the value of ammonia recovered as feed stock was deducted from the cost of production of melamine and if no credit has been taken for ammonia, the same shall be made before issuing the final finding.

(v) Issues have been raised by various interested parties on the issue of taking the import data from IBIS source. Further, it has been claimed that the authority should

take into account the data from the primary sources for calculation of rightful volume of import.

(vi) The interested parties have reiterated their comments made earlier with regard to reconsideration of the APM price for natural gas for production of subject product. It has also been stated that the analysis of export price should not be based on assumption price of domestic industry.

(vii) It has also been stated that how the entire exports from subject countries have been treated as dumped exports.

(viii) It has also been submitted that for the purpose of complication consumption of NIP of and the injury analysis, the cost sheet of urea be drawn considering the market price of ammonia during the POI and NIP for Melamine should be arrived at on the basis of such computed cost of urea.

(ix) It has been submitted that the objective analysis has not been done to examine the casual link between the alleged dumping and injury.

(x) In view of significant increase in the exchange rate for US \$ in the post POI as compare to exchange rate during the POI, the definitive duty, if at all required to be imposed should be recommended on the basis of reference price in the Indian rupees.

Examination by the Authority:

37. The issues raised by the interested parties have been examined herein below by the Authority considering the legal provisions and practice being adopted by the Authority.

38. As regards the argument that GSFC is unable to meet the demand in India and there is wide demand supply gap, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is to redress unfair trade practices and not restrict imports of the product under consideration in Indian market. It is further noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The Authority refers to its past consistent position in this regard and also relies upon the decision of the CESTAT in the matter of *DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority*. If the exporters want to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirement at a price equivalent to normal value but not at dumped prices. During the investigation proceedings, it is noted that GSFC is setting up an integrated fertiliser and petrochemicals

complex at Dahej, Gujarat, at an investment of Rs 7,000 crore for which Detailed Project Report has been done. Land allocation and tendering are in progress. The complex will have a capacity to 40,000 mtpa of melamine apart from other fertilizer and petrochemical production capacity. Hence the company is taking steps to cater the demand of the Indian market. Further the impact of dumped imports shall be on commercialization of additional capacities being set up in India by GSFC as the producers may not even find market for the additional capacities that are coming up due to presence of dumped imports in the market. The Authority also notes that the domestic industry argued that if the market for the product under consideration is not fair, its investment shall not be remunerative. The domestic industry argued that, in fact, it would be unviable to set up the plant if the prices of the product remain so unreasonably low.

39. As regards the argument that non confidential version of the petition is not replica of confidential version, it is noted that the interested parties have compared the initiation notification with the non confidential version of the petition. There are lots of steps/discussions involved from filing of petition till the initiation of investigation. All the relevant information is available on record in the public file. The Authority, after considering all the relevant information and after satisfying itself as to the existence of prima facie evidence of dumping, injury and causal link has initiated the subject investigation. It is also noted that the issue with regard to imports made by the petitioner has been challenged by various interested parties and the domestic industry in its written submission provided detailed information with regard to imports made by the petitioner and its justification for consideration as a domestic industry. The issue has been analysed in detail under the relevant headings in this statement findings.

40. As regards exclusion of exports under duty exemption scheme, it is noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

41. As regards the argument that the domestic industry has generated record profits, it is noted that the present investigation relates to Melamine and therefore all the injury analysis has been done based on the data of the melamine product. GSFC is a multi-product company and any statement in the annual reports is not relevant unless it pertains to product under consideration. The Authority notes in this regard that the anti-dumping investigations are product specific investigations and not company specific investigation. The Authority has examined the injury parameters after verification of the records of the domestic industry and after the examination, the injury parameters have been analysed in the subsequent paragraphs.

42. As regards the argument that Cost of sales trend is not reflective of the fluctuation in the international urea prices, the Authority has analyzed the import and export price of Urea of subject countries and compared the same with the cost of domestic industry as can be seen from table below. It is noted that the urea prices considered by the petitioner for determining cost of sales are in fact lower than the international urea prices or prices prevailing in each of the subject countries.

SN	Description	2006-07	2007-08	2008-09	April'09- June'10
----	-------------	---------	---------	---------	----------------------

A	Domestic Industry - Cost (Non-APM)	9,110	10,234	13,457	12,276
	Indexed	100	112	148	135
B	Import price of Urea				
1	India	10,323	12,319	19,646	11,458
2	EU	11,538	13,774	21,074	14,391
3	Indonesia	8,016	5,109	25,686	15,524
4	Iran	5,775	-	-	13,999
5	Japan	14,108	15,852	27,528	17,557
C	Export price of Urea				
1	India	13,230	25,221	30,572	16,523
2	EU	10,302	13,230	22,563	12,613
3	Indonesia	11,079	12,638	29,740	15,816
4	Iran	-	-	-	12,912
5	Japan	52,404	40,969	38,960	43,949

43. As regards arguments with regard to 15 months POI selected by the Authority for the subject investigation, it is noted that same has been selected keeping into account the consistent practice that the POI generally should be closer to the date of initiation and also the fact that it takes into account one full financial year data of the domestic industry.

44. **Examination by the authority on the issues concerning dumping and injury raised by interested parties subsequent to public hearing and disclosure statement:**

- i. Pursuant to receipt of comment from the interested parties, the injury parameters and determination of non-injurious price have been re-checked before taking the same on board in this Final Finding. Further the injury analysis have been carried out objectively and conclusions on the injury and casual link have been arrived at and is mentioned at appropriate headings. It is incorrect to state that cost of production is lower than selling price or the NIP determined for the subject goods is lower than the net selling price of the subject goods. It is further noted that all the injury information has been analyzed objectively and the conclusions have been drawn after examination of all parameters concerning injury and causal link in the appropriate headings. The Authority further notes that the cost of production as given within AR does not include profit and further it does not relate to POI.
- ii. With regard to principles concerning normal value is concerned, the same has been clearly spelt out in the appropriate headings. The normal value has been held confidential for the reason that some of the elements of construction constructed

normal value have been taken from the confidential information made available by domestic industry and therefore this information have been kept confidential.

- iii. On the issue of determination of non-injurious price for the domestic industry, it is noted that the same has been arrived at after following computed in terms of the principles laid down as per Annexure III of the Anti Dumping Rules as amended. The Authority further notes that the value of ammonia recorded as field stock has been deducted from the cost of production of Melamine for determination of NIP.
- iv. On the issue of taking into account the import data covering volume and value of subject goods from subject countries, it is noted that the same has been taken from IBIS data as the said data captures higher volume of subject goods from subject countries during the POI. For this purpose a comparison of the data containing imports of subject goods have been made from both the sources.
- v. On the issue of correctness of export price taken into account for the purpose of determining dumping margin and injury analysis, it is noted that the same has been rechecked.
- vi. On the issue of reconsideration of APM price for natural gas for production of subject goods while determining non-injurious price, it is noted that this issue has already been dealt in the appropriate paragraphs. With regard to the issue of the volume of dumped imports of subject goods from subject countries, it is noted that positive dumping margins have been determined with regard to subject goods from all subject countries. In view of this, all the volume of subject goods from subject countries have been treated as dumped imports in the injury analysis.
- vii. On the issue of monopolistic behavior of the domestic industry, the authority has examined the contentions of all interested parties and after examination, it is noted that the purpose of antidumping duty, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in general interest of the country. With regard to allegation of creating a monopolistic environment, it is noted that the authority determines dumping, injury and causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry before recommending the imposition of anti dumping duties or otherwise. From the antidumping rules, it is not borne out that a company, even if monopolistic, is prohibited from requesting to the authority actions against the unfair imports
- viii. On the issue of duty structure for this subject finding, the contentions of both the domestic industry as well as importers and users have been considered. It has been noted that in the earlier case of the same product from China PR, the anti dumping duties have been imposed on reference price basis. In the subject case

also, it is considered appropriate to follow the same duty structure in this subject final finding.

Cumulative assessment of injury

45. As per annexure-II (iii) of Anti Dumping Rules, in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%.

46. With a view to assess the conditions of competition between imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product, the Authority notes that -

- a. The subject goods have been imported from the subject countries under the same tariff classification;
- b. The Authority has found that the imported subject goods are commercial substitutes of the domestically produced melamine.
- c. The information furnished to the Authority gives a reasonable indication that the exports made from the subject countries compete in the same market, as these are similar products.
- d. None of the interested parties have argued that cumulative assessment of the effects of dumped imports on the domestic industry shall not be appropriate in the present case.

47. Therefore, For the purpose of injury analysis the Authority has examined cumulative effect of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on production, capacity utilization, sales, prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

48. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. Annexure II of AD Rules provides for objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped

imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

49. Since positive dumping margins have been established for the imports from the subject countries, therefore, entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examination.

50. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties.

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic industry:

51. Transaction-wise information of imports of subject goods was called from DGCI&S and the same was compared with the information provided by the IBIS (secondary sources). After the detailed examination, it was decided to take into account the information from IBIS as it had reported higher volumes.

Import, Demand, Volumes and Market share:

52. The demand of the product in the Country has been assessed as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

Imports from subject countries and other countries

53. It is noted that imports of the subject goods from subject countries has increased significantly in absolute terms during the injury period while the imports from other countries have been much less throughout the injury period and has increased marginally.

Market Share of imports

54. The imports of subject goods from subject countries, countries attracting anti dumping duties and other countries are mentioned below. It is noted that volume of imports of subject goods from subject countries have increased significantly during the injury period in absolute terms. The imports of subject goods from other countries are insignificant. In terms of market share of total imports, it is noted that share of imports of subject goods from subject countries have marginally declined while that of imports from other countries excepting countries attracting anti dumping duty have declined.

Particulars	Units	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Imports	MT	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153
EU	MT	302	662	1,144	6,443	5,154
Indonesia	MT	2,787	6,665	989	3,801	3,041
Iran	MT	453	2,761	1,421	7,420	5,936
Japan	MT	980	840	280	2,160	1,728
Subject Countries	MT	4,522	10,928	3,833	19,824	15,859
China already ADD duty	MT	1,612	5,104	8,867	8,894	7,115

Other Countries	MT	140	430	220	223	178
Market share in Imports						
EU	%	4.81	4.02	8.85	22.26	22.26
Indonesia	%	44.42	40.49	7.66	13.13	13.13
Iran	%	7.22	16.77	11.00	25.64	25.64
Japan	%	15.62	5.10	2.17	7.46	7.46
Subject Countries	%	72.07	66.38	29.67	68.50	68.50
China already ADD duty	%	25.70	31.00	68.63	30.73	30.73
Other Countries		2.23	2.61	1.70	0.77	0.77

Demand particulars:

55. It is noted that the demand for the product under consideration increased throughout the injury period with a decline in 2008-09 which could be due to recession.

Particulars	Units	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Imports	MT	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153
EU	MT	302	662	1,144	6,443	5,154
Indonesia	MT	2,787	6,665	989	3,801	3,041
Iran	MT	453	2,761	1,421	7,420	5,936
Japan	MT	980	840	280	2,160	1,728
Subject Countries	MT	4,522	10,928	3,833	19,824	15,859
China already ADD duty	MT	1,612	5,104	8,867	8,894	7,115
Other Countries	MT	140	430	220	223	178
Imports total	MT	6,273	16,463	12,920	28,941	23,153
Sales of Domestic Industry	MT	15,563	14,804	14,115	15,720	12,576
Demand	MT	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
Index demand		100	143	124	205	164

Imports in relation to various parameters:

56. It is also noted that imports of the product under consideration from subject countries increased in relation to production and consumption of the like product in India during the injury period. Further this has also increased in relation to domestic sales in India.

Particulars	Units	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Imports in relation to					
Share in total imports					

EU	%	4.81	4.02	8.85	22.26
Indonesia	%	44.42	40.49	7.66	13.13
Iran	%	7.22	16.77	11.00	25.64
Japan	%	15.62	5.10	2.17	7.46
Subject countries		72.07	66.38	29.67	68.50
Share in Demand					
EU	%	1.38	2.12	4.23	14.43
Indonesia	%	12.76	21.32	3.66	8.51
Iran	%	2.07	8.83	5.25	16.61
Japan	%	4.49	2.69	1.04	4.84
Subject countries		20.71	34.95	14.18	44.39
Share in Production in India					
EU	%	1.97	4.49	8.37	39.00
Indonesia	%	18.17	45.22	7.24	23.01
Iran	%	2.95	18.73	10.40	44.92
Japan	%	6.39	5.70	2.05	13.08
Subject countries		29.48	74.14	28.07	120.01
Share in Sales of Petitioner					
EU	%	1.94	4.47	8.10	40.99
Indonesia	%	17.91	45.03	7.01	24.18
Iran	%	2.91	18.65	10.06	47.20
Japan	%	6.30	5.67	1.98	13.74
Subject countries		29.05	73.82	27.16	126.11

Market share of domestic industry:

57. It is noted that the market share of the domestic industry has declined during the injury period.

Particulars	Units	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Market share in Demand	%				
Subject Countries	%	20.71	34.95	14.18	44.39
EU	%	1.38	2.12	4.23	14.43
Indonesia	%	12.76	21.32	3.66	8.51
Iran	%	2.07	8.83	5.25	16.61
Japan	%	4.49	2.69	1.04	4.84
Other Countries	%	8.02	17.70	33.61	20.41
Sales of Domestic Industry	%	71.27	47.35	52.21	35.20

58. It is thus noted that demand for the product under consideration increased throughout the injury period and has grown significantly during the injury period. Further, imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms during the same period. As a result the market share of the domestic industry declined during the injury period.

Price effect of dumped imports on the domestic industry:

Price undercutting

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. A comparison for product concerned was made between the landed value of imported product from subject countries and the average selling price of the domestic industry for domestic market net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The CIF prices of the subject countries concerned were adjusted for post importation applicable duties. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in each of the subject countries were sold in the Indian market at prices which were lower than the domestic industry's prices. It is thus seen that imports were undercutting the domestic prices.

Particulars	Units	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Landed Value of subject countries	Rs./MT	55,089	54,854	68,602	61,853
Net sales realization	Rs./MT	52,728	59,567	71,937	66,555
Indexed	Trend	100	113	136	126
Price Undercutting	Rs./MT	(2,362)	4,713	3,335	4,702
Indexed	Trend	(100)	200	141	199
EU	Rs./MT	(3,316)	(6,510)	1,134	3,334
Indexed		(100)	(196)	34	101
Iran	Rs./MT	3,219	5,396	11,179	9,099
Indexed		100	168	347	283
Indonesia	Rs./MT	(3,287)	5,578	(3,479)	703
Indexed		(100)	170	(106)	21
Japan	Rs./MT	(2,016)	4,448	(3,398)	710
Indexed		(100)	221	(169)	35
Price Undercutting of subject countries	%	(4.48)	7.91	4.64	7.06
Price Undercutting of subject countries	% Range	Negative	5-15	0-10	0-10
EU		(6.29)	(10.93)	1.58	5.00
Price Undercutting	% Range	Negative	Negative	0-10	0-10
Iran		6.10	9.06	15.54	11.30
Price Undercutting	% Range	0-10	5-15	10-20	5-15

Indonesia		(6.23)	9.36	(4.84)	4.17
Price Undercutting	% Range	Negative	5-15	Negative	0-10
Japan		(3.82)	7.47	(4.72)	3.01
Price Undercutting	% Range	Negative	5-15	Negative	0-10

Price underselling:

60. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. After due examination, it is noted that the landed value of imports from subject countries is significantly below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry

Particulars	Unit	POI
Non injurious price	Rs/MT	***
Landed Value		
Subject countries	Rs/MT	61,853
EU	Rs/MT	63,220
Iran	Rs/MT	57,455
Indonesia	Rs/MT	65,851
Japan	Rs/MT	65,845
Price underselling		
Subject countries	Rs/MT	***
EU	Rs/MT	***
Iran	Rs/MT	***
Indonesia	Rs/MT	***
Japan	Rs/MT	***
Price underselling		
Subject countries - Range	%	15-25
EU	%	10-20
Iran	%	25-35
Indonesia	%	5-15
Japan	%	5-15

Price Suppression

61. It is noted that the Domestic Industry is adversely affected by the reason of price suppression. It is noted that both the cost to make and sell as well as selling price of the domestic industry have increased during the injury period with a slight decline in POI. But the increase in cost to make and sale is more than the increase in selling price of the domestic industry resulting in price suppression. The price suppression is considered significant.

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Landed Price - Subject countries	Rs./MT	55,089	54,854	68,602	61,853

Index	Trend	100	100	125	112
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
Index	Trend	100	111	153	150
Domestic selling price	Rs./MT	****	****	****	****
Index	Trend	100	113	136	126

62. Thus, the information clearly establishes that imports of the product under consideration were undercutting the prices in domestic market and the effect of dumped imports was to suppress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.

Economic parameters of the domestic industry

63. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(i) Production:

64. It is noted that production of the domestic industry declined over the injury period whereas the demand for the product increased by 64% during the same period.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Capacity	MT	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
Production	MT	15,335	14,741	13,655	16,519	13,215
Trend	Indexed	100	96	89	86	86
Demand	MT	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
Trend	Indexed	100	143	124	164	164

(ii) Capacity & capacity utilization:

65. It is noted that capacity installed by the company during the injury period remained the same. It is also noted that petitioner is using the production capacities dedicatedly for the product under consideration. Whereas demand for the product increased during the injury

19826/12-11

period, decline in production led to decline in capacity utilization. Thus, whereas demand for the product increased by about 64%, capacity utilization declined by 14%.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Capacity	MT	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
Production	MT	15,335	14,741	13,655	16,519	13,215
Capacity Utilization	%	102.23	98.27	91.03	88.10	88.10
Trend	Indexed	100	96	89	86	86
Demand	MT	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
Trend	Indexed	100	143	124	164	164

Domestic sales:

66. It is noted that domestic sales of the domestic industry declined over the injury period whereas the demand of the product under consideration increased.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Domestic Sales	MT	15,543	14,804	14,115	15,720	12,576
Trend	Indexed	100	95	91	81	81
Demand	MT	21,836	31,266	27,036	44,661	35,729
% of sales in demand	%	71.18	47.35	52.21	35.20	35.20

(iv) Profitability:

67. The profitability of the domestic industry in respect of domestic like product has been examined only in respect of domestic sales. It is seen that profitability of the domestic industry for the subject goods has been affected adversely during the injury period. In fact, it is noted that from the position of profit during the beginning of the injury period, the domestic industry has suffered losses in POI.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Cost of Sales	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	111	153	150
Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	113	136	126

Profit/Loss	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	124	34	(25)
Profit before Interest & tax	Rs. Lacs	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	108	44	(9)

68. The interested parties argued that despite rising trends of raw material, the company has generated sufficient and record profits. It is, noted that the profitability of the domestic industry declined over the current period. The argument of the interested parties with regard to sufficient or record profits is therefore factually incorrect.

69. It has been alleged that the domestic industry has claimed losses by making cost adjustment to inflate the cost of Urea. It is noted that the same methodology has been adopted for determining profits for the entire injury period. Thus the deterioration in profits is not on account of any possible inflated cost of urea.

70. It has been argued that the utilities consumption of the domestic industry increased in the period of investigation. It is noted that the non-injurious price of the domestic industry has been determined by the considering the optimum consumption of utilities. It is noted that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of profits, cash flow and return on investment even after adjusting the injury to the domestic industry from higher consumption of utilities

(v) **Employment and Wages:**

71. Employment with the domestic industry and wages paid were as follows

Productivity	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Employment	Nos.	62	68	66	62	62
Indexed	Trend	100	110	106	100	100
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	109	130	121	121

72. It is noted that employment has remained unchanged throughout the injury period whereas wages paid have increased.

(vi) **Productivity:**

73. Productivity of the domestic industry was as follows

Productivity	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Productivity per day	MT	44	42	39	38
Productivity per employee	MT/Nos	247	217	207	213

74. It is seen that productivity of the domestic industry was almost at similar levels during the injury period.

(vii) **Return on investments and cash flow:**

75. The return on investment has been determined considering profit before interest and capital employed in of cost of the product. Impact on cash flow has been determined considering profit before depreciation but after interest cost. It is noted that return on capital employed and cash profits have increased in 2007-08 but thereafter significantly deteriorated over the injury period. It is also noted that the performance of the domestic industry with regard to profits and return on capital employed & cash profits moved in same direction and deteriorated adversely during the injury period.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
ROCE	%	****	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	120	65	(13)	(13)
Cash Profit	Rs.Lacs	****	****	****	****	****
Indexed	Trend	100	113	52	15	15

(viii) **Inventories:**

76. It is noted that the inventory of the domestic industry has declined during the injury period.

Stock (Volume)	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI	POI Annualized
Opening	MT	763	538	476	16	13
Closing	MT	538	476	16	815	652
Average	MT	651	507	246	416	332
Sales	MT	15,543	14,804	14,115	15,720	12,576
Inventories equal to no. of days domestic sales	Nos	15	12	6	10	10

(ix) **Growth:**

77. Information with respect to growth in various parameters is given in the table below. It is seen that growth in terms of both volume & price parameters is negative.

Growth	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
In Production	%		(3.87)	(7.37)	(3.22)
In Domestic Sales	%		(4.75)	(4.65)	(10.91)
In Capacity Utilization	%		(3.87)	(7.37)	(3.22)
In Cost of Sales Rs/MT	%		***	***	***
In Selling Price Rs/MT	%		***	***	***
In Profit /Loss Rs/MT	%		***	***	***
In Profit /Loss Rs.Lacs	%		***	***	***
In PBT Rs.Lacs	%		***	***	***
In PBIT Rs.Lacs	%		***	***	***
In ROI %	%		***	***	***

(x) **Ability to raise capital investments:**

78. The domestic industry contended that it has planned capital investment of Rs. 7000 crores, which is for a number of products. This includes substantial capacity expansion for Melamine. The company has argued that it intends to enhance the capacity for Melamine by 40,000 MT. the feasibility report of which suggests that the investment is unviable at a price below Rs. *** per MT(considering the input price prevailing in that period). The domestic industry argued that continued dumping of Melamine is adversely impacting the expansion plan of the company with regard to the product. It is noted that continued dumping of the product and financial losses in the product are bound to adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investments. Though the domestic industry is a multi-product company, the adverse impact on the operating performance of the domestic industry on account of this product could affect the ability of the domestic industry to raise capital investment for the subject goods.

(x) **Level of dumping & dumping margin:**

79. The dumping margin established hereinabove in respect of subject countries are quite significant and above the de-minimus level.

Causal Link

80. The Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It was found as follows.

(i) **Imports from third countries:**

81. The Authority has collected the transaction-wise imports data of the subject goods. From the information available on record, the Authority notes that imports from the

countries other than subject countries are either at higher prices or import volume is below the prescribed limit or the country is already attracting ADD.

(ii) **Contraction in demand:**

82. The Authority notes that the demand for the product under consideration has shown significant improvement during the injury period. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

(iii) **Changes in the pattern of consumption:**

83. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change, nor there is any quantified allegation in this regard. The investigation so far has not shown existence of alternate competing products and possible injury being caused by such alternate products.

(iv) **Trade Restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers:**

84. It is noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(v) **Developments in Technology:**

85. There is no allegation of developments in technology, nor the investigation so far has shown that possible injury to the domestic industry could have been caused by developments in technology.

(vi) **Export performance:**

86. The petitioner apart from the year 2006-07 has no exports during the injury period. However, the Authority has considered only domestic operations and domestic profitability.

(vii) **Productivity of the Domestic Industry:**

87. There is no material change in productivity of the domestic industry. Possible decline in productivity cannot be the reason for the established injury to the domestic industry.

Level of dumping margin and injury margin:

88. The authority has determined non injurious price considering the records maintained by the company and subsequently verified by the Authority for the inputs procured with regard to production of the product under consideration.

89. The level of dumping margins and injury margins as determined are mentioned below. It is thus noted that these levels are considered significant.

	Unit	EU	Iran	Indonesia	Japan
Dumping Margin	US\$/MT	***	***	***	***
Dumping Margin	Range %	25-35	25-35	20-30	40-50
NIP	Rs./MT	***	***	***	***
Exchange Rate	Rs./US\$	47.88	47.88	47.88	47.88
NIP	US\$/MT	***	***	***	***
Landed Value	US\$/MT	1,320	1,200	1,375	1,375
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***	***
Injury Margin	Range %	10-20	25-35	5-15	5-15

Conclusion on Injury and causation

90. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from subject countries at the absolute level. The market share of dumped imports in total demand of subject goods has also increased significantly. It is also noted that the dumped imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market. It is also determined that the dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price undercutting, price suppression and price underselling. Further, the dumping margins from subject countries have been determined and are considered significant.

91. It is noted that dumped imports of subject goods from subject countries have had significant adverse price effect which in turn have led to significant deterioration in profits and return on investments. The domestic industry is suffering losses in period of investigation. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and injury has been caused significantly by price and volume effects of dumped imports from the subject country.

92. The Authority therefore holds that material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

Indian industry's interest & other issues

93. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

94. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the

injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

Recommendations

95. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- (a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below Normal values.
- (b) The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries.
- (c) The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

96. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.

97. With regard to duty structure, keeping into account factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend benchmark/reference form of anti dumping duties, equal to the difference between the amount indicated in the column 8 of the table below and landed value, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central government on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries

Duty Table

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29336100	Melamine	European Union	European Union	Any	Any	1537	MT	USD
2	Do	Do	European Union	Any country other than EU	Any	Any	1537	MT	USD
3	Do	Do	Any country other than EU	European Union	Any	Any	1537	MT	USD
4	Do	Do	Iran	Iran	Any	Any	1446	MT	USD
5	Do	Do	Iran	Any country other than Iran	Any	Any	1446	MT	USD
6	Do	Do	Any country other than Iran	Iran	Any	Any	1446	MT	USD
7	Do	Do	Indonesia	Indonesia	Any	Any	1537	MT	USD
8	Do	Do	Indonesia	Any country other than Indonesia	Any	Any	1537	MT	USD
9	Do	Do	Any country other than Indonesia	Indonesia	Any	Any	1537	MT	USD
10	Do	Do	Japan	Japan	Any	Any	1537	MT	USD
11	Do	Do	Japan	Any country other than Japan	Any	Any	1537	MT	USD
12	Do	Do	Any country other than Japan	Japan	Any	Any	1537	MT	USD

98. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

99. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority